देश का Darpan News TV
FASTWAY
Comming Soon
काम करने के लिए सम्पर्क करें

दैनिक समाचार पत्र

देश का दर्पण न्यूज

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व महाराष्ट्र से प्रकाशित

वर्ष-5, अंक:177 | जयपुर, मंगलवार, 09 सितम्बर 2025 | मूल्य : 5.00 पेज:

अब आपके मोबाइल पर डिजिटल अखबार
प्रदेश के ताजा समाचार
अपने लेख एवं समाचार भेजे

सम्पादक : उमेन्द्र राजपूत
7014997449, 9636058201
Email : deshkadarpannews@gmail.com
web.: www.deshkadarpannews.co

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया तोहफा, 80 पिंक बस सेवा शुरू

एजेंसी

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाई जाने वाली 80 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।यह कार्यक्रम सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर आयोजित किया गया, जहां उन्होंने 1,065 बसों में ई-टिकट सुविधा का भी उद्घाटन किया। इस पहल से बिहार के विभिन्न जिलों में महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 1,065 बसों में ई-टिकटिंग सुविधा लागू करने का शुभारंभ किया तथा द्वितीय चरण में नई 80 पिंक बसों का लोकार्पण भी किया। इन बसों में केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं। इन पिंक बसों के परिचालन से महिलाओं का सफर ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगा और उन्हें आवागमन में काफी सहूलियत होगी। साथ ही ई-टिकटिंग की व्यवस्था से राज्य के लोगों को विभिन्न जगहों पर यात्रा करने में सुगमता होगी।

बिहार में विशेष तौर पर महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जा रही है। इस बस में सभी तरह की सुविधाएं रहती हैं। बस में कंडक्टर के साथ-साथ कोशिश यह होती है कि इस बस का ड्राइवर भी महिला ही रहे, जिससे सुरक्षा बनी रहे। पिंक बस की कंडक्टर सविता कुमारी ने बात करते हुए कहा, यह सरकार की अच्छी पहल है, इससे महिलाओं को काफी फायदा मिलेगा। बस में महिलाओं के लिए सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया है। बस में मेडिकल सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

कंडक्टर पिंकी कुमारी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बस में तीन कैमरे लगाए गए हैं। दूरदराज जाने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अगर बस में गर्भवती महिला सफर करती है तो उनके लिए अलग से सीट है, साथ ही कंडक्टर भी उनका विशेष ध्यान देंगी।उन्होंने आगे बताया कि महिलाओं से सफर के दौरान फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी। सभी बसें राज्य के विभिन्न जिलों में चलेंगी, जिन्हें कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को वाराणसी में मॉरीशस के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे

एजेंसी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 11 सितंबर को मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ नदेसर स्थित एक तारांकित होटल में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे । वैश्विक कूटनीतिक के दृष्टि से महत्वपूर्ण इस वार्ता की तैयारियां चल रही है। जिला प्रशासन के अफसरों के अनुसार, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम अब तीन दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। मेहमान प्रधानमंत्री 10 सितंबर की शाम काशी पहुंचेंग। वे 11 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे और देर शाम गंगा आरती देखेंगे। 12 सितंबर की सुबह श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वाराणसी से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 सितंबर को दोपहर वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में उनका दौरा लगभग डेढ़ घंटे का रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे एयरपोर्ट से वायुसेना के हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन से कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग के जरिये सीधे नदेसर स्थित ताज होटल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री करीब डेढ़ बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने सोमवार से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त के अनुसार इस विशेष सफाई अभियान का उद्देश्य न केवल प्रधानमंत्री के आगमन से पहले शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, बल्कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे शहर में स्वच्छता और सौंदर्यकरण का संदेश देना भी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम को नोडल विभाग बनाया गया है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव : पप्पू यादव

पूर्णिया । पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो सभी दलों को 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए।पप्पू यादव ने सोमवार को आईएएनएस से खास बातचीत में कहा,'उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी पार्टी के अपने अधिकार हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में बेहतर करने का समय है। वह एक विद्वान और पूर्व न्यायाधीश हैं और मेरा मानना है कि पार्टी से ऊपर उठकर सबके हित में न्याय करेंगे। संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो सभी दलों को 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए।'बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर पप्पू यादव ने कहा, 'इस बात का फैसला प्रभारी और पार्टी के अध्यक्ष को करना है। कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी ने समाज में एक उम्मीद और विश्वास जगाने का काम किया है। मेरा मानना है कि बिहार अब बदलाव की ओर बढ़ गया है। बिहार की जनता राहुल गांधी के विचारों और संघर्षों के साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि बिहार ही देश को दिशा देने का काम करेगा। इस बार बिहार में बदलाव आएगा और बिहार विरोधी, युवा विरोधी तथा गरीब विरोधी सरकार को समाप्त करने का काम करेगी।' उन्होंने आगे कहा, ÷कांग्रेस के लिए हमेशा से ही विचारधारा और मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। पार्टी के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। कांग्रेस हमेशा सामने के लक्ष्य को देखकर काम करती है और आज कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा एनडीए है। राहुल गांधी के लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं बल्कि उनका उद्देश्य 'इंडिया गठबंधन' को मजबूत करना है।' बिहार में कांग्रेस की भूमिका के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, 'कांग्रेस बिहार में छोटे या बड़े भाई की भूमिका में नहीं है।

पंजाब बाढ़ : भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी

जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद

एजेंसी

चंडीगड़। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पंजाब के कई जिलों के गांवों में बाढ़ का कहर है। इस संकट में भारतीय सेना 'ऑपरेशन राहत' के तहत रेस्क्यू अभियान चला रही है, जिसके जरिए जरूरतमंदों तक खाना, पानी और अन्य जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है।

भारतीय सेना के वज्र कॉर्प्स ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे राहत अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बचाव अभियान से संबंधित कुछ फोटो शेयर किए।उन्होंने एक्स पर लिखा, 'ऑपरेशन राहत'। पंजाब में बाढ़, घर उजड़े, जिंदगियां बिखरीं। निराशा के बीच भारतीय सेना गांव वालों के साथ खड़ी है। परिवारों को बचाते हुए, बुजुर्गों का सहारा बनते हुए, बच्चों को सुरक्षित उठाते हुए, भोजन, पानी और उम्मीद पहुंचाते हुए। हर आलिंगन भरोसे और उम्मीद का बंधन दर्शाता है।' इसके अलावा, वज्र कॉर्प्स ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'हरिके, तरन तारन में सतलुज का पानी बढ़ा तो गांववाले और वज्र कॉर्प्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। बांध को मजबूत किया, दरार पाटी और अनगिनत जिंदगियां सुरक्षित कीं। एक सच्ची मिसाल- एकता, हिम्मत और भरोसे की।' अभी बाढ़ से पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। नदियां उफान पर हैं, जिससे हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए जा चुके हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। जबकि लाखों हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पंजाब इस बार मानसून में बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

बालू खनन मामले में पश्चिम बंगाल के चार जिलों समेत 22 ठिकानों पर ईडी का छापा

एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में अवैध बालू खनन व तस्करी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार सुबह झाड़ग्राम, पश्चिम मिदनापुर, उत्तर 24 परगना और कोलकाता सहित चार जिलों में एक साथ 22 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, झाड़ग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर 1 और 2 ब्लॉक में कई बालू खनन कारोबारियों के घरों पर ईडी और केंद्रीय बलों की संयुक्त टीम पहुंची। सबसे पहले जांच एजेंसी ने कारोबारी शेख जहीरुल अली के घर पर छापा मारा। उन पर लंबे समय से सुवर्णरेखा नदी से अवैध बालू खनन और तस्करी का आरोप है। बताया गया कि जहीरुल अली पहले गांव की सिविल पुलिस में कार्यरत था, लेकिन नौकरी छोड़कर बालू खनन का धंधा शुरू किया। उसके घर और गाड़ियों की तलाशी के दौरान कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। ईडी को आशंका है कि अवैध बालू खनन कारोबार से कमाया गया पैसा फर्जी कंपनियों और हवाला के जरिए इधर-उधर किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि जहीरुल अली ने भी कई फर्जी कंपनियों के जरिए पैसों की लेन-देन को अंजाम दिया।

इस दौरान बालू खनन कारोबारियों के अलावा उन ट्रक चालकों के घरों पर भी छापेमारी हुई, जो खदानों से बालू ढोते थे। कुछ समय पहले ही नौयाग्राम थाना पुलिस ने इसी मामले में दो ट्रक चालकों–अमरजीत बेरा और दुखीराम बाग को गिरफ्तार किया था। इधर कोलकाता में भी सुबह-सुबह ईडी अधिकारियों ने रीजेंट पार्क इलाके में एक सार्वजनिक बीमा कंपनी के कर्मचारी के घर छापा मारा। आरोप है कि अवैध बालू खनन कारोबार से जुटाया गया पैसा बीमा क्षेत्र में निवेश किया गया। इसके अलावा, जेम्स लॉन्ग सरणी और सखेर बाजार इलाके में जीडी माइनिंग कंपनी के निदेशक के घर पर भी छापेमारी की गई।

मुख्यमंत्री ने दिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद प्रदेश सरकार सजग हो गयी है। अब सरकार प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता व प्रवेश की गहनता से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम गठित की जाएगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। संस्थानों से शपथपत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।

केवल मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित होने की घोषणा भी संस्थानों की करनी होगी। सभी कोर्सों की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच की जाएगी, ताकि छात्रों के साथ कोई धोखधड़ी न हो पाए। जानकारी के अनुसार जो संस्थान बिना मान्यता वाले कोर्स संचालित कर रहे होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच में यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी और छात्रों को पूरा शुल्क ब्याज सहित लौटाना होगा। जांच कमेटियों को 15 दिन में शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य किया गया है। जिलों में गठित कमेटियों की जांच कीमण्डलायुक्त सीधे निगरानी करेंगे। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री घनश्याम शाही और पश्चिम उप्र क्षेत्र के मनोज नीखरा और राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल ने रविवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। श्रीराम स्वरूप विश्वविद्यालय में मान्यता रिन्यू किए बिना विधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे थे। छात्रों ने ऐसी तमाम अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने विद्यार्थियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया था। कई छात्र-छात्राएं घायल हुए थे। अब भी उन चोटिल छात्रों का इलाज हो रहा है। पुलिस के जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ राजस्व विभाग को मिली गड़बड़ी के बाद विश्वविद्यालय के अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ढहाया भी गया है।

मनसा देवी पहाड़ी से गिरे मलबे के चलते हरिद्वार-देहरादून रेल मार्ग अवरुद्ध, कई ट्रेनें निरस्त

एजेंसी

हरिद्वार। तेज बारिश के चलते सोमवार सुबह भीम गोडा काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक पर मनसा देवी पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा आ जाने से रेल यातायात अवरुद्ध हो गया है। रेल ट्रैक बाधित होने से ट्रेनों को निरस्त किया गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह मिट्टी और चट्टानों का मलबे आने से भीमगोड़ा रेलवे सुरंग के समीप रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से बंद हो गया। ट्रैक पर अवरोध आने के कारण कई ट्रेन स्थगित करनी पड़ी हैं तथा कई को ज्वालापुर स्टेशन पर टर्मिनेट करना पड़ा। इनमें ऋषिकेश-कोच्चिवली एक्सप्रेस, हावड़ा- ऋषिकेश एक्सप्रेस, अमृतसर- देहरादून एक्सप्रेस तथा ऋषिकेश-हरिद्वार पैसेंजर सहित कई गाड़ियां शामिल है। उन्होंने बताया कि मलवा आने की वजह से देहरादून-हरिद्वार व ऋषिकेश रेल मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। रेलवे विभाग की टीम मलबा हटाने में जुटी है। काली मंदिर के समीप हुए इस भूस्खलन से आंशिक तौर पर मंदिर भी चपेट में आया और मंदिर के बाहर बना शिवजी का छोटा सा स्थान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गुफा वाले मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस स्थान पर इससे पहले भी कई बार मलवा आने से रेल यातायात बाधित हो चुका है। पूर्व की घटनाओं को देखते हुए इस जगह रेलवे ने लोहे के जाल लगा रखे हैं, जिस कारण मलबा सड़क पर नहीं आया।

एनआईए का जम्मू-कश्मीर के बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा में छापा

एजेंसी

जम्मू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पांच राज्यों और जम्मू-कश्मीर में 22 जगहों पर छापा मारा है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी एक आतंकी साजिश मामले की जांच के सिलसिले में इन स्थानों पर तलाशी ले रही है। अधिकारियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में एजेंसी की कार्रवाई जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

बीजेपी वोट चोरी कर चुनाव जीतती रही, जनता का ईवीएम से भरोसा टूटा - परसादी मीणा

एजेंसी

लालसोट। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस ने अब सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। रविवार को संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांदसेन की बैठक में पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला।

उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर चुनाव जीतती रही है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1.29 लाख फर्जी वोट डाले गए, बावजूद इसके भाजपा मात्र 29 हजार वोटों से जीत सकी। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच छह माह के अंतराल में ही वोटों में भारी अंतर सामने आया। बिहार में एसआईआर अभियान के नाम पर 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, लेकिन एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। राहुल गांधी इस साजिश का खुलासा पहले ही कर चुके हैं।

ईवीएम पर उठाए सवाल

मीणा ने कहा कि जनता का ईवीएम पर से भरोसा टूट चुका है। अब पूरा देश बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया भी निष्पक्ष नहीं रही। चयन समिति से सीजेआई को हटाकर गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को शामिल करना लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

16 सितम्बर को संविधान बचाओ रैली

उन्होंने घोषणा की कि 16 सितम्बर को लालसोट में संविधान बचाओ रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल होंगे।

स्थानीय मुद्दों पर भी साधा निशाना

चिकित्सा सुविधाएँ : कांग्रेस सरकार ने वार्ड स्तर पर जनता क्लिनिक खोली थी, लेकिन इन्हें बंद कर पुराने जिला अस्पताल भवन में शिफ्ट कर दिया गया।

बजरी माफिया :ट्रैक्टर-ट्रॉली रोक दी गई, लेकिन डंपर से अवैध वसूली जारी है। 3,000 की बजरी आज 15,000 में मिल रही है।

हर आयु वर्ग के लोगों की गतिशीलता के सुधार में फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण:जेपी नड्डा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर कहा कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिशीलता में सुधार और उनके जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सोमवार को एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय, स्वस्थ वृद्धावस्था - गिरने और दुर्बलता में फिजियोथेरेपी की भूमिका, वृद्धों में गिरने से बचाव और दुर्बलता के प्रबंधन में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है, जिससे सक्रिय और सम्मानजनक वृद्धावस्था की ओर उनकी यात्रा को समर्थन मिलता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि देश में स्वस्थ वृद्धावस्था पहल के एक अभिन्न अंग के रूप में फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देते रहें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार ने वृद्धजनों के लाभ के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सरकारी अस्पतालों में कई योजनाएं उपलब्ध कराई हैं। लोगों को इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 08 सितंबर को मनाया जाता है ताकि फिजियोथेरेपिस्टों के योगदान को मान्यता दी जा सके, फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को सक्रिय व स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करने में इस पेशे के महत्व को उजागर किया जा सके। यह दिन विश्व फिजियोथेरेपी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 1951 में हुई थी, और यह वैश्विक फिजियोथेरेपी समुदाय की एकता का भी प्रतीक है। इस वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का थीम स्वस्थ उम्र बढ़ना है, जिसमें कमजोरी और गिरने से बचाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह थीम स्वस्थ उम्र बढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए व्यायाम और भौतिक चिकित्सा के महत्व पर जोर देती है, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों में कमजोरी को कम करने और गिरने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सिरोही प्रभारी मंत्री श्री विश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन

जयपुर, 08 सितम्बर। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री श्री के.के. विश्नोई की अध्यक्षता में आत्मा सभागार में अतिवृष्टि से हुए नुकसान एवं बजट घोषणाओं के त्वरित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री विश्नोई ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के सम्बन्ध में अनुपम कार्य किये जा रहे हैं।

उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता के साथ हर सुख दुख में पूर्ण तत्परता के साथ खडी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए आमजन को राहत पहुंचाने की बात कही।प्रभारी मंत्री श्री विश्नोई ने इस दौरान अतिवृष्टि की स्थिति में मकानों, फसलों, और पशुधन के नुकसान की समीक्षा कर अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत बचाव आदि कार्यों को तत्परता से करने के निर्देश दिये साथ ही जिले में जर्जर भवनों, टूटी सडकों आदि की समीक्षा करते हुए मरम्मत के सम्बन्ध में भी शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आमजन के हित के लिए पूर्ण तत्परता के साथ कार्य करें और अलर्ट मोड पर रहे। राज्य सरकार वर्षा प्रभावित लोगां को त्वरित राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान फसल नुकसान, मकान क्षति और पशु हानि आदि की विस्तृत समीक्षा की और प्रस्ताव आदि तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करने की बात भी कही साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार करने तथा वृहद स्तर पर काश्तकारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री विश्नोई ने वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की विभागवार समीक्षा भी की इस दौरान उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को बजट घोषणाओं के सम्बन्ध में समयबद्ध सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जा रहे विभिन्न प्रयास और वृक्षारोपण का कार्य प्रदेश सरकार की महती प्राथमिकता है कोई भी विभाग लापरवाही ना बरतते हुए आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें उन्होंने कहा टैगिंग और पौधां की सार संभाल करते हुए पूर्ण गंभीरता से कार्य किया जाए और सभी के द्वारा सक्रिय सहभागिता निभाई जाए। इस दौरान सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गए निदेर्शों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही देखी

जयपुर, 08 सितम्बर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर डीडवाना के श्री बांगड महिला महावि?द्यालय की छात्राओं ने सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही देखी। इस अवसर पर श्री देवनानी ने वि?द्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की गहन जानकारी दी। उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। वि?द्यार्थियों ने ऐतिहासिक पीतल द्वार पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और विधायक श्री युनूस खां के साथ सामूहिक चित्र लिया। विद्यालय प्रबंधन ने इस ऐतिहासिक अनुभव के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

श्री देवनानी को दैनिक सम्राट की प्रति भेंट

जयपुर, 08 सितम्बर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी को सोमवार को विधानसभा में दैनिक सम्राट समाचार पत्र के सम्पादक श्री उमेश कुमार शर्मा ने समाचार पत्र की प्रति भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और निष्पक्ष तथा जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता समाज को दिशा देने का कार्य करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दैनिक सम्राट पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुद्दढ़ करने में योगदान देगा।

राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित- मत्स्य संबंधी अपराध पर 50 हजार रुपए तक जुमार्ना,अपराधों में आएगी कमी -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर, 8 सितंबर। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक- 2025 विधानसभा में सोमवार को ध्वनिमत से पारित हुआ। इसके अनुसार अब बिना अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ने, विस्फोटक अथवा विष डालकर मछली मारने जैसे मत्स्य अपराधों पर जुमार्ना बढ़ाया गया है। अब तक पहली बार अपराध साबित होने पर 500 रुपए की शास्ति, 3 माह कैद की सजा या दोनों का प्रावधान था। इस शास्ति को अब 25000 रुपए किया गया है। इसी प्रकार दोबारा अपराध सिद्धि पर शास्ति राशि को 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया है। अब दोबारा अपराध करने पर 6 माह की जेल या शास्ति या दोनों का प्रावधान है। इसके बाद भी अपराध करने पर हर अपराध पर यह शास्ति या जेल या दोनों का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि मत्स्य अपराधों में न्यायालय द्वारा अपराधी पर शास्ति लगाए जाने के प्रावधान हैं। इनमें लम्बे समय से शास्तियां नहीं बढ़ाई गई थी। अभी पहली बार अपराध पर शास्ति 500 रुपए की शास्ती लगाई जाती है, जिसे अब 25 हजार रुपए किए जा रहा है। मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य को अधिकृत किया गया है। मूल अधिनियम के सेक्शन 11 में किए पूर्व संशोधन में 100 रुपए शास्ति का प्रावधान था। इसे भी बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया है।

राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025- राजस्थान मसालों के लिए विश्व विख्यातस, अब हर वर्ष आयोजित होगा मसाला कॉन्क्लेव

जयपुर, 08 सितंबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मसालों के उत्पादन और व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही मसालों की समृद्ध परंपरा के लिए विश्व विख्यात है। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला कॉनक्लेव का आयोजन हमारे मसाला उद्योग को नई दिशा व गति प्रदान करेगा। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। साथ ही, इस संबंध में समिति का गठन भी किया जाएगा, जिससे राज्य के मसाला उत्पादकों एवं व्यापारियों को नई संभावनाओं और नए अवसरों का सृजन करने के लिए एक वैश्विक मंच मिल सके।

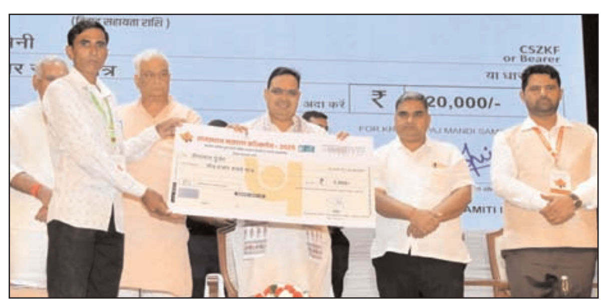

श्री शर्मा सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025 में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में मसाला प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं है। राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मैथी एवं सौंफ उत्पादन में दूसरे और धनिया एवं अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फोर लोकल की अवधारणा मसाला उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों की आय दोगुनी करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी इस योजना के तहत आठ इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

इन इन्क्यूबेंशन सेंटर में कृषि उपज की जांच, छंटाई, ग्रेडिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और ओडीओपी उपज के लिए प्रसंस्करण सुविधा मिल सकेगी, जिससे वे अपने प्रसंस्कृत उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए कई नीतियां लाई गई हैं। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में 1 हजार 497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला— आदि कर्मयोगी अभियान से जयपुर के 177 गांवों का होगा कायाकल्प

जयपुर, 8 सितंबर। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत 8 सितम्बर 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार जयपुर में जिला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में किया गया। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारम्भ किया गया यह अभियान जनजातीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन और अंतिम छोर तक सेवा संतृप्ति सुनिश्चित करने की एक राष्ट्रीय पहल है। अभियान के तहत देशभर के जनजाति-बहुल एक लाख गांवों में 20-20 व्यक्तियों को आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी एवं आदि साथी के रूप में चयनित किया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर जिले के 10 ब्लॉकों के 177 गांवों का चयन किया गया है। जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों के अभिसरण द्वारा इन गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित

रिम्स में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं दिलाएंगी प्रदेश को विशेष पहचान

जयपुर, 8 सितम्बर। विधानसभा में सोमवार को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गत डेढ़ साल में चिकित्सा क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं जिससे राजस्थान अग्रणी राज्य बना है। इसी कड़ी में एम्स की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) स्थापित कर रहे हैं।

सतावी साइड रुँगीबी फुटबॉल अंडर-19 प्रतियोगिता में जीनियस बाल भारतीय स्कूल जयपुर ने मारी बाजी

सीकर

चौगान स्टेडियम में आयोजित सतावी साइड रुँगीबी फुटबॉल अंडर-19 बालक वर्ग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का जोश

और जज्बा देखने लायक रहा। इस प्रतियोगिता में कुल 19 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला जीनियस बाल भारतीय स्कूल जयपुर और शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर के बीच खेला गया। दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीनियस बाल भारतीय स्कूल जयपुर ने सांगानेर की टीम को शिकस्त देकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विजेता टीम को समाजसेवी नरेन्द्र वर्मा (सीकर), जाकिर हुसैन (भरतपुर) और विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष सैन ने ट्रॉफी व सम्मान देकर बधाई दी। टीम की जीत में कप्तान अभिषेक कुमार के नेतृत्व के साथ खिलाड़ियों किशन लाल, तनवीर सिंह, अमन कुमार, विकास कुमार, ऋतिक, यश, योगेश कुमार, रोहित, लकी कुमार, भानु प्रताप और कोच गज्जू माली का अहम योगदान रहा। इस शानदार जीत के साथ जीनियस बाल भारतीय स्कूल जयपुर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और टीम भावना से हर चुनौती को जीता जा सकता है।

सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया: राज्यपाल

जयपुर, 8 सितम्बर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि शिक्षा व संस्कृति से ही संस्कारों का निर्माण होता है। अच्छे संस्कारों से राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनते हैं। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है।

श्री बागडे सोमवार को श्री गिरधारी लाल बिहाणी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित शिक्षा अमृत महोत्सव-शताब्दी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टिकाऊ समाज के निर्माण में सभी की भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं तथा कहा कि

साक्षरता मौलिक अधिकार है। भारतीय संस्कृति, शिक्षा का समर्पण जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। राष्ट्र का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, मानव संसाधनों से होता है। इसके लिये शिक्षा एक जरूरी कदम है। राज्यपाल ने कहा कि हिन्दू धर्म में वसुधैव कुटुम्बकम्‌ में विश्वास रखने की भावना है। हम लोग पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। यही सनातन धर्म है। भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी दूसरे धर्म को कम आंकने या निंदा करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा सोचोगे, वैसा ही बनोगे की अवधारणा होनी चाहिए। विद्यार्थियों में एकाग्रता बहुत जरूरी है। हमारे युवा प्रतिभाशाली बनें, इसके लिये एकाग्रता पर जोर देते हुए उन्होंने महाभारत में अर्जुन ने जिस प्रकार निशाना लगाया, का उदाहरण दिया। श्री बागडे ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ-साथ संस्कारवान व गुणवान बनाये।

अजमेर में जलभराव से प्रभावित क्षेत्र में एक किलोमीटर पैदल चल कर पीड़ितों के पास पहुंची उपमुख्यमंत्री

—घर-घर जाकर जाने जलभराव क्षेत्र के हाल, जन जन की सुनी पीड़ा

—प्रभावित परिवारों को मिलेगा मुआवजा

जयपुर, 8 सितम्बर। अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटने से जलभराव के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर श्री लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

संकट की घड़ी में रेड क्रॉस लोगों के साथ-उपायुक्त

अमृतसर, 8 सितंबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)

अमृतसर की उपायुक्त श्रीमती साक्षी साहनी के निदेर्शानुसार, रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर राशन, तिरपाल, दवाइयाँ और पेयजल पहुँचा रही है। उपायुक्त ने कहा कि संकट की

इस घड़ी में रेड क्रॉस लोगों के साथ है और रेड क्रॉस के स्वयंसेवक मैदान में डटे हुए हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए, अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती अमनदीप कौर ने बताया कि आज धुस्सी बन के निकट घोनेवाल गाँव में रेड क्रॉस स्वयंसेवकों द्वारा प्रभावित परिवारों को टॉर्च, ओडोमा, हाथ-पैर के संक्रमण की दवाइयाँ, राशन किट और विशेष रूप से सौर मोबाइल चार्जर और लाइटें पहुँचाई गईं। उन्होंने बताया कि इन गाँवों में अभी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई है और रात में लोगों की मदद के लिए सौर लाइटें उपलब्ध कराई गई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यह समय एक-दूसरे का साथ देने का है और यह हमारा कर्तव्य भी है। उन्होंने नागरिकों से रेडक्रॉस को अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों तक यह मदद पहुँचाई जा सके।

पुलिस परिवार की ओर से दिवंगत कांस्टेबल चालक के परिजनों को जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सौंपा 6 लाख रुपये की राशि का चैक

देश का दर्पण न्यूज, धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 8 सितम्बर।

धौलपुर पुलिस परिवार की ओर से दिवंगत कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा, जिनका पिछले दिनों ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया, के परिजनों को त्वरित राहत स्वरूप आज 6 लाख रुपये की राशि का चेक प्रदान किया गया। यह राशि धौलपुर पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से किए गए अंशदान से संकलित की गई है। उक्त राशि का चेक सोमवार को जिला पुलिस

अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान द्वारा दिवंगत कांस्टेबल चालक के परिजनों को सौंपा गया। धौलपुर पुलिस परिवार इस दुखद घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है और हरसंभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

फाजिल्का विधायक ने रिश्तेदारों के साथ रह रहे बाढ़ प्रभावित परिवार को राशन वितरित किया

फाजिल्का, 8 सितंबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)

फाजिल्का विधायक श्री नरिंदरपाल सिंह सावना ने बताया कि कल रात उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँव गट्टी नंबर 1 के शिंदर सिंह ने उन्हें संदेश के माध्यम से बताया कि उनका घर पानी से घिर जाने के बाद, वे गाँव हजूर सिंह वाला मंडी में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं और अब उन्हें राशन की सख्त जरूरत है। इसके तुरंत बाद उन्होंने शिंदर सिंह को अपने घर बुलाया और उन्हें राशन और अन्य राहत सामग्री दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के अन्य बाढ़ प्रभावित लोग जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, वे बेझिझक उन्हें बताएँ और वे उनसे 97813-77710 पर फोन पर भी बात कर सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं ताकि उन्हें दवाइयाँ, राशन, पशुओं के लिए चारा और अन्य राहत सामग्री दी जा सके।

विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना ने कहा कि जिले में सरकारी प्राइमरी स्कूल नवां हस्ता कलां, मौजम, मंडी लाधूका और रणा में राहत केंद्र चल रहे हैं, लोग इन राहत केंद्रों में भी पहुंच सकते हैं जहां उनके खाने, इलाज और रहने की सभी व्यवस्थाएं मुफ्त हैं।

विधायक टोंग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

बारिश के कारण ढहे मकानों के मालिकों को मुआवजा दिया गया

अमृतसर, 8 सितंबरः(सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और सरकार बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को सहायता प्रदान करेगी। ये शब्द हलका बाबा बकाला के विधायक दलबीर सिंह टोंग ने पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण भिंडर, खिलचियां, तिम्मोवाल, छज्जलवाड़ी आदि गाँवों में ढहे मकानों का निरीक्षण करते हुए व्यक्त किए।

विधायक टोंग ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनके दुख में भागीदार है और जिनके मकान ढह गए हैं, उन्हें नियमानुसार जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को लगातार राहत सामग्री वितरित कर रहा है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है।

विधायक टोंग ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से लड़ें। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर थोड़ा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गिरदावरी कराने के आदेश जारी कर दिए हैं तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र ही मुआवजा दिया जाएगा।

आरपीएससी अध्यक्ष श्री यू आर साहू ने साझा की परीक्षा आयोजन के सुरक्षा उपायों की अहम जानकारियां

जयपुर, 8 सितंबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री यू आर साहू ने सोमवार को आयोजित प्रेंस कांफ्रेंस में परीक्षा आयोजन तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अहम जानकारियां दी। वर्तमान व्यवस्थाओं को पुख्ता बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्न-पत्र खुला मिलने जैसी अफवाहें फैलाने वाले अपने निहित स्वार्थों के कारण ऐसा करते हैं। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने प्रश्न-पत्रों को सुरक्षित परीक्षा केंद्र पहुंचाने वाले मेटल बॉक्स और 7 लेयर सुरक्षा प्रणाली का प्रदर्शन भी किया। परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों को 7 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ लेमिनेटेड मेटल बॉक्स में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। एकल प्रश्न-पत्र मय उत्तर-पत्रक (ओएमआर शीट) को पहले एक पारदर्शी प्लास्टिक पॉलीपैक में सील किया जाता है।

देश का दर्पण
जयपुर, मंगलवार
09.09.2025

डॉ0 आदित्य प्रकाश, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, सिवान के अध्यक्षता में बैठक आयोजित

सीवान संवाददता मसरूर अहमद

सीवान में आज दिनांकः 08 सितम्बर, 2025 को डॉ० आदित्य प्रकाश, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, सिवान के अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का जिला समन्वय समिति का बैठक आयोजित किया गया।*

1. सिवान जिला में दिनांकः 16 सितम्बर, 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा दिनांकः 19 सितम्बर, 2025 को मॉप-अप दिवस का आयोजन किया जाना है।

कार्यक्रम के पूर्व सभी संबंधित विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस.) को दिनांकः 14 सितम्बर, 2025 तक ड्यू लिस्ट अद्यतन करने का निदेश दिया गया। 2. जनसंख्या के आधार पर निर्धारित लक्ष्य के आलोक में सभी प्रखंडों में कार्यक्रम पूर्व आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सिवान को दिया गया।
3. कृमि संक्रमण के बचाव, इलाज एवं फायदे के बारे में प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया।
4. जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा बताया गया कि बच्चों के जिन्दगीं का सवाल है, सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी सहभागिता निभाएं तथा निर्धारित लक्ष्य के आलोक में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। साथ ही, सरकारी विद्यालयों सहित निजी विद्यालयों में भी शत-प्रतिशत अच्छादन सुनिश्चित करें।

बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सिवान, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सिवान, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सिवान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सिवान, शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंडों से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा अन्य सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, न्याय दिलाने का जताया भरोसा, जिलाध्यक्ष ने एसडीपीओ से बात कर कार्रवाई की माँग की, एसडीपीओ ने कहा कि शीघ्र होगी गिरफ्तारी

सीवान संवाददता मसरूर अहमद

सीवान जिला अन्तर्गत महाराजगंज,मे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज दुघी टोला स्थित मुन्ना यादव के घर पहुँचा। विगत 2 सितंबर को मुन्ना यादव की गुमटी पर हत्या कर दी गई थी।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुन्ना यादव के पिता शंकर यादव, भाई हरिलाल यादव, सुनील यादव एवं अन्य परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर ढाढस बढ़ाया। लगभग 45 मिनट तक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार के बीच रहा, पूरी बात को गौर से सुना। पीड़ित के पिता शंकर यादव ने बताया कि यहीं गुमटी पर मुन्ना यादव की हत्या कर दी गई। मृतक मुन्ना यादव के दो छोटे-छोटे बच्चे एवं पत्नी बेसुध हैं। पूरी बात सुनकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने महाराजगंज एसडीपीओ अमन कुमार से दूरभाष पर बात कर दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की माँग की। एसडीपीओ ने जिलाध्यक्ष से कहा कि एक आरोपी संदीप कुमार की गिरफ्तारी हुई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर कोशिश कर रही है। आरोपी चाहे जहाँ भी होंगे, बच नहीं पाएंगे, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। जिलाध्यक्ष ने एसडीपीओ से त्वरित कार्रवाई की माँग की।

प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला पार्षद प्रदुमन राय, पूर्व प्रमुख अशोक कुमार सिंह,रमेश उपाध्याय, मेराज अहमद, संतोष पाण्डेय, अमित कुशवाहा, रवि कुमार शामिल थे।

कॉन्स्टेबल भर्ती-2025 एडमिट कार्ड 11 सितंबर से होंगे डाउनलोड

देश का दर्पण न्यूज
संवाददाता सुरेन्द्र कुमार सोनी

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा 13 सितम्बर को दूसरी पारी में और 14 सितंबर दोनों पारियों में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभ्यर्थी 9 सितंबर से अपने परीक्षा केंद्र, जिले और पारी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। ई-प्रवेश पत्र 11 सितंबर 2025 से अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं।

परीक्षा से जुड़े अहम निर्देश

परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्रवेश पत्र के साथ अपना हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) लाना जरूरी है।

एडमिट कार्ड पर दिए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा। नीले या काले रंग की स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाएं। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है।

सहायता और संपर्क

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी राजकॉम के हेल्पलाइन नंबर 7340557555 या 9352323625 पर और विभाग के संपर्क नंबर 0141-2821597 या ईमेल पर सम्पर्क कर सकते है।

प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता, मांग के अनुसार यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की सभी जिलों में आपूर्ति- कृषि मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता है एवं सभी जिलों में मांग के अनुसार यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की आपूर्ति की गई है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि उर्वरकों के वितरण एवं आपूर्ति में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 एवं 2025 में चूरू जिले में यूरिया की मांग अनुसार आपूर्ति करवाई गई एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से डीएपी उर्वरक की आपूर्ति प्रभावित हुई। चूरू जिले के साथ प्रदेश में डीएपी की आंशिक कमी को देखते हुए डीएपी के वैकल्पिक उर्वरक एसएसपी एवं एनपीके की आपूर्ति कृषकों को की गई। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर की कालाबाजारी करने वालो पर सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किये जा रहे है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान सरकार के दो साल से भी कम के कार्यकाल में 117 औचक निरीक्षण किये गए जबकि गत सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी औचक निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं 423 नमूने, 80 सीजर, 64 एफआईआर की कार्यवाही भी वर्तमान सरकार द्वारा की गई जो अब तक की सर्वाधिक है।

न्यायालय के आदेशानुसार गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा दिया जाना प्रतिबंधित - पंचायतीराज मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। पंचायतीराज मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा दिया जाना प्रतिबंधित है। श्री दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक के नियमों एवं न्यायालय के प्रतिबन्ध के कारण चरागाह भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले विधायक श्री सुभाष मील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार एवं ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार गुणावगुण के आधार पर आबादी हेतु भूमि का आवंटन किया जाता है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बसे लोगों को सरकार समयझसमय पर नियमानुसार पट्टे भी जारी कर रही है।

तहसील विजयनगर के ग्राम धांधड़ा बारानी तथा गोमावाली बारानी की चकबंदी की अधिसूचना 21 अगस्त, 2025 को जारी - संसदीय कार्य मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि तहसील विजयनगर के ग्राम धांधड़ा बारानी तथा गोमावाली बारानी की चकबंदी की अधिसूचना 21 अगस्त, 2025 को जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एक संपूर्ण प्रक्रिया के तहत संपन्न होने वाली चकबंदी की कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी के लिए किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। श्री पटेल प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का राजस्व मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत चकबंदी की कार्यवाही की जाती है। जिसके तहत सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिसूचना जारी की जाती है। इससे पहले विधायक श्री सोहन लाल नायक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि तहसील विजयनगर के ग्राम धांधड़ा बारानी तथा गोमावाली बारानी का चकबन्दी कार्य समुचित प्रक्रियाओं के तहत अभिलेख कार्य सूची संख्या 01 ता 08 का कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने को प्रतिबद्ध- सहकारिता मंत्री

जयपुर, 8 सितंबर। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर उपज खरीदने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसके लिए स्थानीय मांग के अनुसार एमएसपी खरीद केंद्र खोले जाते हैं तथा काश्तकारों को समय पर भुगतान के लिए प्रयास किए जाते है। श्री कुमार प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर उपज की खरीद मांग के आधार पर की जाती है। काश्तकार को परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय कार्यालयों द्वारा तारीख दी जाती है जिससे वे अपनी उपज को खरीद केंद्रों पर लाकर एमएसपी पर बेच सकते है। इसके लिए विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में मूंगफली और मूंग की खरीद निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा की गई।

इससे पहले विधायक श्री रामकेश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि सवाईमाधोपुर जिले में राजफैड द्वारा रबी 2025-26 में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से सरसों की 1034.50 क्वि. व चने की 8166 क्वि. खरीद एमएसपी योजनान्तर्गत की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रबी 2025-26 में भारत सरकार द्वारा सरसों के लिए 1322360 मी. टन व चने के लिए 546255 मी. टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों के विरुद्ध राजफैड द्वारा प्रदेश में रबी 2025- 26 के लिए सरसों की 70107.35 मी. टन व चने की 54336.04 मी. टन खरीद की गई है।

उन्होंने जानकारी दी कि रबी 2025-26 में बाजार भाव समर्थन मूल्य की दर से अधिक होने के कारण किसानों द्वारा एमएसपी योजनान्तर्गत जिन्स विक्रय नहीं की गई है।

लंबित जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी हो रहे - ऊर्जा मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 31 दिसम्बर, 2023 तक कुल 1486 जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन एवं 574 आवेदन मांगपत्र जारी करने हेतु लंबित थे। राज्य सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 के पश्चात 31 अगस्त 2025 तक कुल 1213 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी जारी किये गये। शेष लंबित जमा मांगपत्र वाले आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं।

विधायक श्री विक्रम सिंह जाखल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में 31 दिसम्बर, 2023 तक लंबित कृषि कनेक्शन आवेदनों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक प्रदेश में 1 लाख 59 हजार 29 कृषि कनेक्शन जारी किये गये। जिनका जिलेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। श्री नागर ने बतया कि लंबित जमा मांग पर आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। अन्य योजनाओं जैसे बूंद-बूंद फव्वारा एवं डिग्गी योजना इत्यादि के मांगपत्र तुरन्त प्राथमिकता से जारी कर कृषि कनेक्शन वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। इसी प्रकार सामान्य योजना में सामान्य श्रेणी के 22 फरवरी, 2022 के पश्चात के लंबित पंजीकृत आवेदकों के मांगपत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कटऑफ डेट के अनुसार जारी किये जाएंगे।

उन्होंने जानकारी दी कि इनके अतिरिक्त कृषि कनेक्शन नीति-2017 बिन्दु संख्या 7.1.2 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम-'ए' एवं 'सी' योजना के तहत 33/11 केवी सब-स्टेशनों, जहां कुसुम-ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित एवं प्रचालित (उङ्के२२ङ्गल्लीा) किये जा चुके है एवं भविष्य में भी 33/11 केवी सब-स्टेशनी पर कुसुम-'ए ' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा सयंत्र उङ्के२२ङ्गल्लीा किये जाने हैं, ऐसे कुसुम-ए' एवं 'सी' के सौर ऊर्जा सयंत्रों के उङ्के२२ङ्गल्लीा होने के पश्चात, सब-स्टेशनों पर लंबित सभी कृषि कनेक्शन जिनके मांगपत्र जमाएं आवेदित है, वहां कुसुम-'ए ' एवं सी के सौर ऊर्जा सर्वों की क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता पर जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। फ्इइ-299 आदेश की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के लंबित जमा मांगपत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

लैंड वेलिडेशन एक्ट से प्रदेश में आसान बनेगी उद्योगों की राह - उद्योग मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश की आर्थिक मजबूती एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की बेशकीमती भूमि सस्ती दर पर उद्योगों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं इससे सम्बंधित अन्य विषयों के आसान स्पष्टीकरण के लिए लैंड वेलिडेशन एक्ट लाया जाएगा, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा जैसी समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। इस एक्ट के अंतर्गत नियम बनाकर पेनल्टी एवं कन्वर्जन जैसे आवश्यक विषयों को प्रदेश के हित में लागू किया जाएगा। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में स्थापित 44 औद्योगिक क्षेत्रों में से 40 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के नियम का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने बताया कि इन 40 औद्योगिक क्षेत्रों का नियोजन वर्ष 2011 से पूर्व हुआ था एवं उस समय गैर औद्योगिक उद्देश्य की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं थी तथा शेष 4 औद्योगिक क्षेत्र वर्ष 2011 के बाद से नियोजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 14 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उपयोग की सीमा 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी। इससे पहले विधायक श्री गुरवीर सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि रीको व आरएसएमआईडीसी (रीको की पूर्ववर्ती संस्था) द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उद्देश्य के लिए अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत का निर्धारण 27 जून, 2011 के कार्यालय आदेश द्वारा किया गया है।

04 मई, 2018 के कार्यालय आदेश से 14 औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक उपयोग की सीमा 20 प्रतिशत तक बढ़ाई गई।

राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न

जयपुर, 08 सितम्बर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम की प्रगति, जिला स्तरीय कार्ययोजनाओं एवं नोडल विभागों के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। चयनित जिलों को बजट आवंटन और पुनर्विनियोजन से जुड़े विषय भी एजेंडे में शामिल रहे। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और सतत मॉनिटरिंग के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियाँ सक्रिय रहें और उपखण्ड स्तर पर नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समयबद्ध कार्ययोजना के अनुसार लागू किया जाए, विभागों के बीच समन्वय सुदृढ़ किया जाए और पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चलाकर अधिकतम लाभार्थियों तक पहुँचा जाए। साथ ही वित्तीय प्रावधानों और बजट उपयोग की नियमित समीक्षा कर कार्यक्रम का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुँचाया जाए। आयोजना विभाग के निदेशक श्री विनेश सिंघवी ने बताया कि पंच गौरव कार्यक्रम को राज्य सरकार ने फ्लैगशिप योजना घोषित किया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों से कार्ययोजनाएँ प्राप्त कर उनका परीक्षण संबंधित विभागों से कराया जा चुका है। उन्होंने बैठक के एजेंडा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

गोरा बादल स्टेडियम का चालीस प्रतिशत कार्य पूर्ण, शेष हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से करवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन - युवा मामलात एवं

जयपुर,8 सितम्बर। युवा मामलात एवं खेल मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नगर परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा संवेदक के माध्यम से गोरा बादल स्टेडियम का 40 प्रतिशत रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा शेष कार्य को करवाये जाने हेतु हिन्दुस्तान जिंक से एमओयू की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री सिंह प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार नगर परिषद चित्तौड़गढ़ ?द्वारा उक्त स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए निविदा आंमत्रित की गई थी। जिसमें 40 प्रतिशत रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कर शेष कार्य हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर परिषद चितौडगढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक के बाद प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसके उपरांत निविदा आमंत्रित कर रिनोवेशन का कार्य शुरू कर दिया गया था, परन्तु नगर परिषद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थिति के चलते यह कार्य वर्तमान में बंद हैं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का शेष कार्य हिंदुस्तान जिंक के सीएसआर फंड के माध्यम से करवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इससे पहले विधायक श्री चंद्रभान सिंह चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में युवा मामलात एवं खेल मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल स्टेडियम स्थित है।

विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात

राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान और संयोजक रविन्द्र चौधरी ने भर्ती में 296 चयनितों को नियुक्ति देने ,रक भर्ती सहित ग्रुप बी,सी,डी भर्तियों से इंटरव्यू समाप्त करने , लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने ,पीटीआई भर्ती 2021 में पुनः डीवी करवाने के साथ वंचितों को अवसर देने सहित बेरोजगारों की प्रमुख 10 मांगों को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मांग पत्र सौंपा है बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष हनुमान किसान ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की युवा हितेषी सोच के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिसके लिए प्रदेश के युवाओं को अलग से स्किल कोर्स भी करवाया जाएगा

।आरपीएफ पाली द्वारा स्कूली बच्चों में चलाया गया पत्थरबाजी एवं ट्रेस्पासिंग के संबंध में जागरूकता अभियान

श्रीमान ज्योति कुमार सतीजा, महानिरीक्षक-उ.प.रे. एवं श्री नीतीश शर्मा, वरि. मंडल सुरक्षा आयुक्त-जोधपुर तथा श्री सी पी मिधा, सहायक सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन मे दिनांक 08.09.25 को आरपीएफ पाली के उप निरीक्षक राकेश कुमार, द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में जागरूकता अभियान चलाते हुए स्टाफ के साथ पाली शहर के रूपरजत संस्कार मिशन स्कूल पाली में स्कूली बच्चों को रेलगाड़ी पर पत्थरबाजी नहीं करने, रेलवे लाइन पर गिट्टी /पत्थर नहीं रखने, चलती ट्रेन या रेल एरिया में सेल्फी नहीं लेने, छत/पायदान पर यात्रा नहीं करने, रेलवे लाइन तथा बंद रेलवे फाटक को अनाधिकृत रूप से पार नहीं करने और पशुओ को रेलवे ट्रैक से दूर रखने आदि की समझाइश किया। आरपीएफ के अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को समझाया कि ट्रेन पर पत्थर बाजी करना रेलवे लाइन पर गिट्टी या पत्थर आदि रखना रेल परिसर में अथवा चलती ट्रेन में सेल्फी लेना/जानलेवा स्टंट करना, रेल परिसर में अथवा ट्रेनों में धूम्रपान करना एवं नशे का सेवन करना, रेलवे ट्रैक तथा बंद रेलवे फाटक को पार करना, तथा पशुओं को रेलवे ट्रैक के पास चराना खतरनाक है, यह न केवल जान माल को गंभीर खतरा उत्पन्न करता है अपितु यह रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में भी आता है जिसमें दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जा सकती है।

प्रदेश में 31 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित- जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विभाग ?द्वारा प्रदेश में 31 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 24 आवासीय विद्यालय एवं 2 मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा विद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती की जाती है। श्री खराड़ी प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री लक्ष्मण द्वारा इस संबंध में पूछे गए मूल प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

बौद्धिक दिव्यांग गृह आवासनी मृतका का नियमानुसार किया गया दाह संस्कार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जयपुर, 8 सितम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि जामडोली स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह में पिछले दिनों मृतक आवासनी का अंतिम संस्कार पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त, 2016 को सीमा द्वितीय आवासनी को बौद्धिक दिव्यांग गृह (बालिका विंग) जामडोली जयपुर में प्रवेश दिया गया। 26 मार्च, 2025 को इस आवासनी की तबीयत खराब होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 29 अप्रेल 2025 को रात्रि 10:30 बजे मृत्यु हो पर जाने के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर उक्त आवासनी के माता-पिता के अज्ञात होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही के लिए जामडोली थाने को 30 अप्रेल 2025 को सूचित किया गया। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त आवासनी के शव का 5 मई, 2025 को पोस्टमार्टम पश्चात पुलिस द्वारा सुपुर्दगी करते ही उसी दिन 5 मई को दाह संस्कार की कार्यवाही की गयी। श्री गहलोत ने कहा कि जयपुर के जामडोली स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग गृह में मानसिक रूप से विमंदित बच्चों को रखा जाता है। इन बच्चों की प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा 27 सितंबर 2021 को जारी सर्कुलर के नियमों के अनुसार ही आवासनी का दाह संस्कार किया गया। उन्होंने बताया कि मृतका की मृत्यु अस्पताल रिपोर्ट के अनुसार छङ्कद्वी१ फीरस्र१३१८ ळ१ू३ क्ल्लाीू३ङ्गल्ल (ढल्ली४ङ्गल्लं) के कारण हुई।

रिंटू ने बारिश के कारण रुके हुए विकास कार्यों का किया शुभारंभ.

अमृतसर, 08 सितंबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के विधानसभा उत्तर क्षेत्र के प्रभारी करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण विकास कार्य रुके हुए थे, जिन्हें अब शुरू कर दिया गया है। रिंटू ने कहा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बारिश के कारण जो भी समस्याएँ हुई हैं, उनका समाधान किया

जाएगा। रिंटू ने आज वार्ड संख्या 9 क्षेत्र में शास्त्री नगर गोपाल मंदिर के पास गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से टूटी गलियों की समस्या से जूझ रहे थे। अब उनकी यह समस्या दूर हो जाएगी। गलियों का निर्माण जल्द पूरा होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। रिंटू ने इस क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर साहिल सागर, बॉबी सरीन, गुरिंदर गोरा, जसविंदर सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

करमजीत सिंह रिंटू ने विकास कार्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ग्राम पंचायत चांद एवेन्यू सेक्टर 2 की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण सड़कों का निर्माण कार्य रुक गया था। इस अवसर पर रिंटू ने पंचायत सदस्यों से भी मुलाकात की और बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने पंचायत सदस्यों को आश्वासन दिया कि इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच वीना मेहरा, अध्यक्ष अजय नंदा, पंच राकेश खन्ना, चंदन पाल सिंह, राकेश पाठक, संदीप लाहौरिया, सारथी मेहरा, महेश मुखीजा, डॉ. पुंज, प्रणव धवन सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित थे।

19वीं बटालियन बीएसएफ ने बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गाँव में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया

फाजिल्का, 8 सितंबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)
आज, सीएपी 2025-26 के अंतर्गत, 19वीं बटालियन बीएसएफ ने सीमावर्ती गाँव गुलाबा भैनी (जो भारत-पाक सीमा से मात्र 30 मीटर की दूरी पर स्थित है और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है) में एक विशेष बाढ़ राहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर गुरुद्वारा साहिब में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर, श्री गुंजन कुमार शाह, द्वितीय आईसी, 19वीं बटालियन बीएसएफ, श्री गौरव यादव, डीसी (क्यूएम), डॉ. एस. आई. शाइन (एसी/एमओ) और इंस्पेक्टर प्रोसन सैकिया, ऑफ कंपनी कमांडर ए कंपनी बीओपी जीजी-1 उपस्थित थे। डॉ. विकास नड्डा (एमबीबीएस, एमओ) और डॉ. राजवीर कंबोज (एमबीबीएस, एमओ) ने सिविल अस्पताल फाजिल्का के दो फार्मासिस्टों और 19 बटालियन यूनिट मुख्यालय के दो नर्सिंग सहायकों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान कीं। इस शिविर से लगभग 173 लोगों को लाभ हुआ, जिनमें 80 पुरुष, 70 महिलाएं और 23 बच्चे शामिल थे। लाभार्थियों में ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे थे। बीएसएफ द्वारा आयोजित यह चिकित्सा शिविर बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ

बैंडबाजों की धुनों के साथ रथ में सवार होकर निकले भगवान वासपूज्य

जुरहरा, जिला डीग रेखचन्द्र भारद्वाज: कस्बे में रविवार को जैन समाज के पावन दशलक्षण पर्व के समापन पर स्थानीय दिगंबर जैन समाज के द्वारा क्षमावाणी पर्व परम्परागत तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जैन धर्मावलंबियों के द्वारा एक-दूसरे से क्षमा याचना कर आपस में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी गई। स्थानीय जैन समाज धर्मावलम्बियों के द्वारा दिगम्बर जैन मन्दिर में पूजा-अर्चना कर बोलियां लगाई गईं। क्षमावाणी पर्व के अवसर पर बैण्ड-बाजों व विभिन्न धार्मिक व सामाजिक झांकीयों के साथ कस्बे में भव्य रथयात्रा निकाली गई। जिसमें भगवान वासुपूज्य, रावण दरबार में अंगद, भारत-माता, विद्याभारती विद्यालय द्वारा जैसी करनी वैसी भरनी नाटक सहित विभिन्न झांकीयां मेले की शोभा बढा रही थीं। रथयात्रा कस्बे के दिगम्बर जैन मन्दिर से शुरू होकर चौपडा बाजार, मैन बाजार, बस स्टैण्ड से होते हुए नसियाजी इन्द्रकुटी पंहुची जहां भजन संध्या व अभिषेक आदि के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्षमावाणी पर्व के अवसर पर निकाली गई शोभयात्रा में कस्बा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कस्बे के जैन धर्मावलम्बी शामिल हुए। शोभयात्रा के उपरांत सभी ने वैरभाव को छोडकर मिल जुलकर रहने का संकल्प लिया। क्षमावाणी में सकल जैन समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। वहीं सास-बहू ने एक दूजे से गले लगकर, बेटे ने पिता के पैर एवं छोटों ने बड़ों के पैर छूकर एवं सामूहिक रूप से मिलकर साल भार में की गई गलतियों की क्षमा मांगी।

राजेश भारती और मधु गोयल "मधुल" का राजस्थान के झुंझुनू में हुआ सम्मान

कैथल (कृष्ण प्रजापति): साहित्य जगत के लिए गौरवपूर्ण क्षण तब आया जब राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था "शब्दाक्षर" (पंजीकृत) की कैथल इकाई के जिलाध्यक्ष राजेश भारती और जिला साहित्य मंत्री मधु गोयल "मधुल" को राजस्थान के ऐतिहासिक नगर झुंझुनू में आयोजित तीन दिवसीय वार्षिक साहित्योत्सव में सम्मानित किया गया।

यह सम्मान समारोह संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्र और राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष डॉ. दया शंकर जांगिड़ की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। समारोह के दौरान दोनों साहित्यकारों को राजस्थानी परंपरा अनुसार पगड़ी पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, मोतियों की माला पहनाकर, स्मृति-चिह्न व पुस्तकों से सम्मानित किया गया। यह क्षण उपस्थित सभी साहित्यप्रेमियों के लिए प्रेरणादायी रहा। साहित्योत्सव के दौरान मधु

गोयल "मधुल" की नई काव्य-कृति कुछ पन्ने बचपन के का लोकार्पण भी किया गया। इस पुस्तक में बचपन की यादों, संस्कारों और समाज से जुड़े अनुभवों को संवेदनशील शब्दों में पिरोया गया है। पुस्तक विमोचन के समय साहित्यकारों व पाठकों ने मधुल की रचनात्मकता की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए मूल्यवान योगदान बताया। इस अवसर पर राजेश भारती और मधु गोयल "मधुल" ने अपनी-अपनी कविताओं का काव्य-पाठ भी प्रस्तुत किया। इनके काव्य पाठ ने श्रोताओं के मन को छू लिया और सभा में बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उपस्थित साहित्यप्रेमियों ने दोनों रचनाकारों की सराहना करते हुए कहा कि कैथल की धरती साहित्य साधना में निरंतर नए आयाम जोड़ रही है। यह सम्मान न केवल राजेश भारती और मधु गोयल "मधुल" के साहित्यिक योगदान का प्रमाण है, बल्कि कैथल जिले के लिए भी गर्व का विषय है। दोनों ही साहित्यकार "साहित्य सभा कैथल" के सक्रिय सदस्य हैं और वर्षों से कविता, साहित्य व सामाजिक चेतना को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इस भव्य साहित्योत्सव में देशभर से आए रचनाकारों, साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया।

इंदिरा हैप्पी स्कूल खैरथल में आर पीएफ थानेदार ने दी रेलवे सुरक्षा संबंधी जानकारी

खैरथल अमित शर्मा

खैरथल – इंदिरा हैप्पी स्कूल खैरथल में आर पी एफ अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को रेलवे सुरक्षा संबंधी जानकारी दी इंस्पेक्टर बी पी सैनी ने बताया की रेलवे ट्रैक से गुजरे नहीं जानवरों को भी ट्रैक से क्रॉस न करवाएं चलती ट्रेन में कोई पैंथर बाजी न करे न किसी को करने दे 120 किलोमीटर की गति से ट्रेन आती है ट्रैक पार करते समय रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज का उपयोग करे बच्चो ने उनके निर्देशों को ध्यान से सुना और पालना करने का संकल्प लिया यह जानकारी स्कूल निदेशक पंकज खुराना ने दी आर पी एफ अलवर एस एच ओ बी पी सैनी, ए एस आई मनोज कुमार व सी टी रामकिशन मीना मौजूद रहे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को विधानसभा में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने संत स्वामी आत्माराम लक्ष्य की पेनोरमा निर्माण के भूमि आवंटन के लिए आभार जताया। इस दौरान विधायक श्री रामसहाय वर्मा, रैगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.एल. नवल सहित प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य मौजूद रहे।

ओबीसी बिग्रेड की कोर कमेटी की बैठक सम्पन्न, 43 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा पिछड़ा वर्ग : राजेंद्र

कैथल (कृष्ण प्रजापति): ओबीसी बिग्रेड की कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक स्थानीय दादरी गेट स्थित संगठन के कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने की। बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर ने कहा कि ओबीसी बिग्रेड अब 27 प्रतिशत नहीं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर 43 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि जब 15 प्रतिशत लोगों को साढ़े 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है, तो हरियाणा में 43 प्रतिशत ओबीसी को केवल 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्लास-1 व क्लास-2 नौकरियों में जो आरक्षण 15 प्रतिशत है, उसे बढ़ाकर सरकार को 43 प्रतिशत करना चाहिए। राजेंद्र तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण बिना मांगे ही दे दिया, जिससे 50 प्रतिशत की सीमा पहले ही टूट चुकी है। अब पिछड़ा वर्ग अपनी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ओबीसी बिग्रेड का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन 16 नवंबर को हिसार स्थित कबीर भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब एक हजार कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस सम्मेलन में शासन-प्रशासन, पंचायत, निकाय चुनाव और बजट में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग उठाई जाएगी।

पुलिस अफसरों ने निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए

लखनऊ। अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवे) प्रकाश डी. द्वारा (पीएटी) परीक्षा के दृष्टिगत तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा अभ्यर्थियों से संवाद स्थापित कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

इस अवसर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे लखनऊ सुधा सिंह, पुलिस अधीक्षक, रेलवे लखनऊ रोहित मिश्रा, क्षेत्राधिकारी, रेलवे (द्वितीय) हृषिकेश यादव, स्टेशन अधीक्षक अरविंद बघेल सहित रेलवे, आरपीएफ एवं जीआरपी के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों हेतु हेल्प डेस्क, होल्डिंग एरिया, पेयजल व चिकित्सा जैसी सुविधाओं का अवलोकन किया गया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पेट्रोलियम एसोसिएशन फरीदकोट ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.50 लाख रुपये दान किए

फरीदकोट, 8 सितंबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए, पेट्रोलियम एसोसिएशन फरीदकोट ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उपायुक्त श्रीमती पूनमदीप कौर को 1.50 लाख रुपये की राशि सौंपी।

इस अवसर पर, उपायुक्त ने एसोसिएशन के सदस्यों की समाज सेवा और मानवीय पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा दिया गया योगदान अत्यंत मूल्यवान होता है। यह राशि केवल दान नहीं है, बल्कि उन परिवारों के लिए नई आशा की किरण है, जिन्हें बाढ़ के कारण अपने घर, नौकरी, कृषि आदि का भारी नुकसान हुआ है।

उपायुक्त ने आगे कहा कि यह राशि बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता, खाद्य सामग्री, कपड़े, दवाइयाँ और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के प्रशासन के प्रयासों को और मजबूत करेगी। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों, उद्योगपतियों और व्यापारियों से इस कठिन समय में मानवता की सेवा के लिए आगे आने की अपील की।

पेट्रोलियम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी यदि किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो वे जिला प्रशासन और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को हर संभव सहायता प्रदान करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी गुरजीत सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कांग्रेसी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर हो रहे है खुश:– मदन राठौड़

जयपुर,8 सितंबर 2025। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर खुश हो रहे है। 4 सितंबर को नगर निकाय उपचुनावों के परिणाम में 4 वार्डों में से 1 वार्ड में कांग्रेस जीत पाई, 3 पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, इसके बावजूद कांग्रेसी नेता खुश होकर ताल ठोक रहे है। राठौड़ ने बताया कि निकाय एवं विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने बहुमत से जीत दर्ज करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि जनता का विश्वास आज भी भाजपा के सुशासन, विकास और पारदर्शिता पर कायम है। जबकि कांग्रेस प्रदेश के साथ देशभर में जनता के बीच अपना जनाधार खो चुकी है। ना कांग्रेसी नेताओं की कोई साख है ना ही जनता कांग्रेसी नेताओं पर विश्वास कर पा रही है।

प्रदेश में पिछले 2 सालों में कुल 80 उपचुनावों में से 59 में भाजपा की जीत यह प्रमाणित करती है कि कांग्रेस की कथित जीत केवल एक राजनीतिक दिखावा है।

श्री हंस ने अजनाला विधानसभा क्षेत्र के सुल्तान महल गाँव में बाढ़ पीड़ितों के लिए तिरपाल बाँटे

अजनाला, ड्ड8सितंबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पूरा ज़िला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिन-रात काम कर रहा है, वहीं कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रभावित परिवारों की देखभाल के लिए आगे आ रहे हैं। ये शब्द पंजाब भूमि विकास एवं वित्त निगम और एससी विंग माझा जोन के प्रभारी श्री रविंदर हंस ने आज अजनाला विधानसभा क्षेत्र के सुल्तान महल गाँव में बाढ़ पीड़ितों को तिरपाल बाँटते हुए व्यक्त किए और ग्रामीणों को स्थिति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान पहले ही आदेश दे चुके हैं कि बाढ़ से फसलों सहित सभी तरह के नुकसान का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि पानी उतरने के बाद फसलों को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक विशेष गिरदावरी भी करवाई जाएगी और किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की भी मांग की है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को निराश नहीं करेगी। श्री हंस ने कहा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ हैं और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। श्री हंस ने बताया कि गाँव सुल्तान महल की कुल आबादी 652 है और यहाँ लगभग 150 घर हैं और यहाँ रहने वाले सभी परिवारों तक राहत सामग्री भी पहुँचाई जा रही है।

जिला निष्पादन समिति की बैठक का हुआ आयोजन

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया)8 सितम्बर। जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में हुआ। बैठक में एनएएस सर्वे, नामांकन, आधार एवं जनाधार प्रमाणीकरण, बोर्ड परीक्षा परिणाम, बालिका शिक्षा, मॉडल स्कूल समीक्षा, आईसीटी लैब की समीक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास, समग्र शिक्षा विभिन्न कार्यों की प्रगति के संबंध में एजेंडावार जानकारी ली

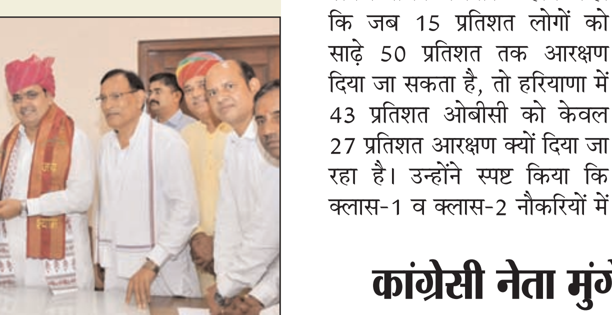

और आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शैक्षिक उन्नयन के लिए नियमित रूप से तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा दिया जाये। विद्यालयों की आईसीटी लैब को नियमित उपयोग कर क्रियाशील रखा जाये। आरकेएसएमबीके के अन्तर्गत विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। सभी स्कूलों में गहन मॉनीटरिंग की जाये ताकि एमडीएम, शैक्षिणक योजनाएं, परीक्षा परिणाम और शैक्षिक उन्नयन हो व अन्य सुधार हो। उन्होंने कहा कि जिले में अत्यधिक वर्षा होने के कारण जर्जर हुए विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। जर्जर हालत वाले कक्षा कक्षों में किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाए। बैठक में मिड-डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में मिड-डे मील की नियमित निगरानी, मेन्यू के अनुसार भोजन वितरण तथा स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बाल वाहिनियों के सुरक्षा पैरामीटर की जांच कर मानकों पर खरी उतरने वाली वाहिनियों को ही संचालित करने के निर्देश दिए।

जिला निष्पादन समिति की समीक्षा के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जो भी योजनाएं लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। एडीपीसी महेश मंगल ने पीपीटी के माध्यम से समस्त एजेंडे संबंधी बिंदुबार जानकारी दी।

10 सितम्बर से होगा खाद्यान्न वितरण

हरदोई। जिला पूर्ती अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह सितम्बर, 2025 में 10 सितम्बर से 25 सितम्बर 2025 के मध्य वितरण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधाराकों के मध्य प्रति कार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूँ व 21 कि०ग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2025 के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु0-18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रु0-54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 02 कि०ग्रा० गेहूँ व 03 कि०ग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 कि०ग्रा०) का वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुबिधा उपलब्ध रहेगी, खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण का कार्य प्रातः 08.00 बजे से 12.00 बजे तक एवं दोपहर 02.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर 2025 होगी

राज्यपाल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राज्यपाल की उनसे यह शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने इस दौरान राष्ट्रपति से राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया।

कांग्रेस ने की बाढ़ में डूबी फसलों के लिए मुआवजे की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मांग की कि दिल्ली के लगभग 50 गांवों के किसान, जिनकी खड़ी फसलों का बाढ़ के पानी डूबने से हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने से हुए नुकसान का प्रति एकड़ 1,00,00 रुपये वित्तीय मुआवजा दिया जाना चाहिए। आर्थिक संकट झेल रहे अधिकतर किसानों ने कर्ज लेकर अपनी भूमि पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते है, बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद किसानों के समक्ष गंभीर हालात पैदा हो रहे है। देवेंद्र यादव ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण यमुना में हथिनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी और लगातार बारिश के कारण निचले तटीय क्षेत्रों में पानी भरने से कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब भी बारिश, बाढ़ या ओलावृष्टि के कारण फसल का नुकसान होता था, तो किसानों को 25,000-50,000 रुपये प्रति एकड़ तक की त्वरित वित्तीय राहत प्रदान की जाती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश केजरीवाल सरकार ने 11 साल से अधिक समय में किसानों की पूरी तरह से उपेक्षा की और अब वर्तमान में भाजपा की सरकार किसानों की फसल डूबने से बर्बाद होने के बाद हुए नुकसान की अनदेखी करके किसानों के लिए वही रणनीति अपना रही है।

मुख्यमंत्री ने की शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करें और तय समयसीमा पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दें। उन्होंने पूर्ण एवं लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा, भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि

शालीमार बाग में जलभराव वाले क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग प्वॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे। बाजारों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों की सतत समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने एक अकाउंट पर साझा की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शालीमार बाग विधानसभा से विधायक हैं।

हत्या के मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले में पैरोल लेकर फरार हुए आरोपित को करीब छह साल बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान मुजफ्फरनगर, यूपी निवासी नौशाद (42) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित को लोनी इलाके से गिरफ्तार किया है। दोहरे हत्याकांड में 26 जुलाई 2013 को नौशाद व बाकी अन्यों को उम्र कैद की सजा हो गई थी। जेल में सजा काटने के दौरान वर्ष 2019 में आरोपित पैरोल पर बाहर आया और उसने कभी कोर्ट या जेल का रुख नहीं किया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि 27 मार्च 2006 को पड़ोसियों ने घर में घुसकर पप्पू और उसकी मां अनीशा की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपितों ने पप्पू की बहन हिना को चाकू से गोद दिया था। उसे भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जीएसटी सुधारों पर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संसदीय दल की कार्यशाला में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में हालिया सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव में जीएसटी को और सरल, पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

भाजपा ने बताया कि कराधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। एक प्रभावी कर व्यवस्था उत्पादन को बढ़ावा देती है, उपभोग को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्र के खजाने को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में किए गए सुधार इन सभी

उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। आठ साल पहले, 2017 में, एक राष्ट्र, एक कर के विजन के तहत जीएसटी लागू किया गया था, जिसने वैट और विभिन्न जटिल करों की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर एक एकीकृत बाजार की स्थापना की। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार में सुगमता आई और अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता व मजबूती बढ़ी। पार्टी ने बताया कि 2014 से पहले, कई सरकारें जीएसटी लागू करने में असफल रहीं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने न केवल इसे लागू किया, बल्कि पूरे देश में आम सहमति के साथ इसे प्रभावी बनाया। आज जीएसटी करदाता आधार 66 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह 18 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मासिक संग्रह अब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो 2017 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। डेलॉइट के सर्वेक्षण के अनुसार, 85 प्रतिशत व्यवसाय, विशेष रूप से एमएसएमई, जीएसटी से संतुष्ट हैं, जो इस सुधार की सफलता को रेखांकित करता है। भाजपा ने बताया कि नए सुधारों में खाद्य, दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी, उल्टे शुल्क की समस्याओं का समाधान और छोटे व्यवसायों, निर्यातकों व स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। ये कदम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने, व्यापारियों को सशक्त करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करने की दिशा में हैं। मासिक संग्रह में वृद्धि अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है।

केंद्रीय मंत्री बुधवार को गाजियाबाद में अत्याधुनिक रासायनिक प्रयोगशाला का करेंगे उद्घाटन

एजेंसी

नई दिल्ल। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी 10 सितंबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान गाजियाबाद में नवनिर्मित अत्याधुनिक राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) का उद्घाटन करेंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक यह प्रयोगशाला 1977 में स्थापित हुई थी, जिसने विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण किये हैं। अब अत्याधुनिक रूप से विकसित किये जाने के बाद यहां पैक किया हुए पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री, एल्युमीनियम और तांबे से बने एनामेल्ड और इंसुलेटेड तार, कोयला, पेट्रोलियम कोक, बिटुमेन, एनामेल पेंट, एंटी-स्किड उत्पाद, रेत और बजरी जैसे निस्पंदन माध्यम, साथ ही सफेद और रंगीन चाक का परीक्षण किया जाएगा। यह रासायनिक प्रयोगशाला भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट, जल, धातु, मिश्रधातु, कागज़, प्लास्टिक, जैविक उत्पाद और उर्वरकों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के परीक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। मंत्रालय के मुताबिक यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनमें परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर (एएएस), इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज़्मा-परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी (आईसीपी-एईएस), ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर (ओईएस), गैस क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री (जीसी-एमएस), उच्च-प्रदर्शन द्रव क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी), और आयन क्रोमैटोग्राफ शामिल हैं। ये उन्नत सुविधाएं प्रयोगशाला को विविध क्षेत्रों में परिष्कृत और अत्यधिक सटीक विश्लेषण करने में सक्षम बनाती हैं। प्रयोगशाला विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और उद्योगों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परीक्षण सहायता भी प्रदान करती है, जिससे वैज्ञानिक और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है।

दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावित के लिए 52 ट्रक राहत सामग्री पंजाब भेजी

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे 52 ट्रकों को रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त पंजाबवासियों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पंजाब की मिट्टी की महक दिल्ली की रगों में रची-बसी है। हम एक ही परिवार हैं और जब पंजाब संकट में है तो दिल्ली उसका दर्द बांटने के लिए उसके साथ खड़ी है। उन्होंने सभी मंत्रियों, अधिकारियों और स्वयंसेवकों का हृदय से आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इतने कम समय में भोजन सामग्री से लेकर हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान से भी बात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि इस कठिन घड़ी में दिल्ली पंजाब के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक परिवार की तरह हर पंजाबवासी के

साथ खड़ा है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 'प्राकृतिक आपदा' की इस कठिन घड़ी में दिल्ली भाजपा संगठन द्वारा सेवा के दायित्व का पालन करते हुए आज पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 52 ट्रकों में राहत सामग्री रवाना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदेश के लोगों पर भयंकर प्राकृतिक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं चलता, परन्तु ऐसे समय में मदद का हाथ बढ़ाना ही सच्ची मानवता है। भाजपा सरकार और संगठन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों तक तुरंत राहत पहुंचे और उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। इस मौके पर दिल्ली सरकार के कई मंत्री और भाजपा नेता मौजूद रहे।

यमुना जलस्तर में दो मीटर की गिरावट, अभी भी खतरे के निशान से ऊपर

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली में खतरे के निशान ऊपर बह रही यमुना का जलस्तर तीसरे दिन भी गिरावट जारी है। दोपहर 1 बजे यमुना का जलस्तर 205.50 दर्ज किया गया है। एक समय 207.48 पर पहुंचे यमुना के जलस्तर में लगातार तीन दिनों से गिरावट जारी है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्स पर करते हुए जानकारी दी कि अब यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाला संपर्क मार्ग सुलभ हो गया है। तीन दिन पहले जलभराव के कारण इस मार्ग को आवागमन के लिए रोक दिया गया था, जबकि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के अंदर मेट्रो बिना किसी रूकावट के चल रही थी।

हालांकि यमुना अब भी खतरे के निशान 205.33 से ऊपर है, जिससे उसे सटे इलाकों जलमग्न है। यमुना किनारे बसे लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रशासन राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था राहत शिविरों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। इसके साथ-साथ जिन घाटों पर पानी कम

लगातार कर रहा है। दिल्ली सरकार ने भी राहत शिविरों में सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। दिल्ली नगर निगम हो रहा है, वहां सफाई कर रहा है। लोगों को बीमारियों से बचने के लिए जरूरी उपाय भी निगम द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली के सुल्तानपुरी में ऑनलाइन जुआ रैकेट का पर्दाफाश, नौ गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बाहरी जिले के सुल्तानपुरी इलाके में मुंबई से चलाए जा रहे एक बड़े अवैध ऑनलाइन जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

जिला विशेष टीम (डीएसटी), बाहरी जिला और सुल्तानपुरी थाने की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सरगना सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 85,320 रुपए नकद, 6 कंप्यूटर सेटअप और अन्य जुआ सामग्री बरामद की। मामला दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 5 सितंबर को हुई, जब डीएसटी की टीम सुल्तानपुरी में गश्त पर थी। विश्वसनीय सूचना मिली कि डीडीए मार्केट, पी-ब्लॉक के पास कुछ लोग ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बाद, इंस्पेक्टर विक्रम के नेतृत्व में टीम ने स्थानीय पुलिस के

सहयोग से छापा मारा। घटनास्थल पर 9 संदिग्धों को ऑनलाइन जुआ खेलते पकड़ा गया। वे भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, पुलिस ने उन्हें तुरंत दबोच लिया। पुलिस उपायुक्त (बाहरी जिला) सचिन शर्मा ने बताया कि यह रैकेट मुंबई से संचालित हो रहा था। आरोपी संदिग्ध लिंक, क्यूआर कोड और ओटीपी के जरिए लोगों को फंसाते थे। वे गूगल ऑथेंटिकेटर के माध्यम से लिंक भेजते थे। पीड़ितों को क्यूआर कोड स्कैन कर ऐप इंस्टॉल करने और ओटीपी डालकर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने को कहा जाता था। ऐप इंस्टॉल होने के बाद, उपयोगकर्ताओं को असली पैसे से पॉइंट खरीदकर जुआ खेलने के लिए लुभाया जाता था। दो-तीन महीने चलाने के बाद संचालक ऐप को बंद कर देते और नए लिंक के जरिए अपराध को अंजाम देते थे। सरगना भुवेंद्र उर्फ भूपेंद्र (48 वर्ष, सुल्तानपुरी निवासी) पहले भी जुआ एक्ट के 5 मामलों में फंस चुका है। अन्य आरोपियों में सूरज (26, अमन विहार), मयंक (20, सुल्तानपुरी), राहुल (26, अमन विहार), रोहन (23, सुल्तानपुरी), राजेंद्र गुप्ता (40, अमन विहार), धर्मवीर (33, सुल्तानपुरी), दिलशाद अहमद (33, सुल्तानपुरी) और राजेश गुप्ता (32, सुल्तानपुरी) शामिल हैं। छापे में बरामद सामान में 85,320 रुपए नकद (जुए से कमाई), 6 मॉनिटर, 6 सीपीयू, 6 कीबोर्ड, 6 माउस और अन्य उपकरण शामिल हैं। डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, बाहरी जिले में संगठित अपराध और जुए के खिलाफ सतर्कता बरती जा रही है। सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में सक्रिय गश्त करें। नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में जीते सात पदक, केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 16 अगस्त को चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (आईईएसओ-2025) में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक हासिल किए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन (आई-जीवाईएम)

रिपोर्टर श्रेणी में भी तीसरा पुरस्कार मिला। विजेता छात्रों में लुधियाना के रयांश गुप्ता को स्वर्ण, रजत और आई-जीवाईएम तृतीय पुरस्कार मिला। कपूरथला के चारुव्रत बैंस को 2 रजत और 1 कांस्य, जयपुर की अपम निधि पांडे को 1 रजत और दिल्ली की प्रियांशी घनघास को 1 कांस्य प्राप्त हुआ। छात्रों को प्रोफेसर देवेश वालिया और प्रोफेसर हेमा अच्युतन ने मार्गदर्शन दिया तथा डॉ. जगवीर सिंह पर्यवेक्षक के रूप में साथ रहे।

प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे से पहले सिसोदिया ने बाढ़ राहत के लिए मांगे 60 हजार करोड़ रुपए

एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र ने विनाशकारी बाढ़ के बाद पंजाब की मदद के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को राज्य का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल राहत की घोषणा करने का आग्रह किया और याद दिलाया कि पंजाब के लोगों का आधिकारिक तौर पर 60 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं।

सिसोदिया ने चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ÷मेरा आकलन है कि व्यापक बाढ़ के कारण बहुत बड़े पैमाने पर राहत की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी भी पंजाब आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री मान से बात की और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब का दौरा किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पंजाब आज मदद की उम्मीद कर रहा है। केंद्र को जल्द ही कुछ घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप नेताओं ने हाल ही में तरनतारन और कपूरथला सहित बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था। कुछ खेतों में दो फुट से ज?यादा रेत जमा हो गई है। किसान पूछ रहे हैं कि इसे कैसे हटाया जाएगा। अगर यह जमा रहा तो उपजाऊ जमीन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। सिसोदिया ने ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसानों को अपने खेतों से रेत हटाने की अनुमति देने के लिए एक विशेष नीति पर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी नीतियां वर्तमान में बिना अनुमति के खनन पर रोक लगाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मान ने मुझे आश्वासन दिया है कि

इस पर ध्यान दिया जाएगा। अगले 2-3 दिनों में, जब वह अपनी बीमारी से ठीक हो जाएंगे तो इस नीति की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आप नेता और स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर राहत कार्यों में लगे हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि मैं खुद कई गांवों में गया, अपनी टीमों का मनोबल बढ़ाया और लोगों से प्रतिक्रिया ली। हर जगह एक ही चिंता है। किसान अपनी फसलों और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

दो घंटे चले सीमा विवाद के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला

नई दिल्ली।) उत्तर-पूर्वी जिले के हर्ष विहार स्थित प्रताप नगर में शुक्रवार रात दो दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में मृतकों की पहचान सुधीर उर्फ बंटी (35) और राधे प्रजापति (30) के रूप में हुई है। दो बाइकों पर सवार हो आए 5-6 आरोपित वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही उप्र और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। उप्र पुलिस दिल्ली का इलाका बताकर अपना पल्ला झगड़ने लगी। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारी एरिया लोनी का बता रहे थे। करीब दो घंटे तक चले सीमा विवाद के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को दखल देना पड़ा। जिसके बाद हर्ष विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। शुरुआती जांच के बाद हत्याकांड में लोनी के दो सगे भाइयों व उनके साथियों के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल 27 अगस्त को दोनों दोस्तों का आरोपितों से किसी बात पर विवाद हो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि पार्किंग को लेकर कहासुनी के बाद दोनों ओर से गाली-गलौच हो गई थी।

श्री नारायण गुरु जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को याद किया

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु की शिक्षाएं आज भी व्यापक रूप से गूंजती हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'श्री नारायण गुरु की जयंती पर, हम उनके दृष्टिकोण और हमारे सामाजिक व आध्यात्मिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव को याद करते हैं। समानता, करुणा और विश्व बंधुत्व की उनकी शिक्षाएं व्यापक रूप से गूंजती हैं। सामाजिक सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने का उनका आह्वान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री नारायण गुरु को समाज सुधारक, महान संत और दार्शनिक बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज की बुराइयों को दूर करने और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। शाह ने पोस्ट किया, ÷श्री नारायण गुरुदेव एक समाज सुधारक, महान संत और दार्शनिक थे, जिन्होंने अपना जीवन समाज की बुराइयों को दूर करने और हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।

उनके करुणा, समानता और ज्ञान का शाश्वत संदेश भारत को सही राह पर ले जाता है। हम उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हैं।' पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन निस्वार्थ प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी अपनी आत्मा की खुशी के लिए किया जाए, वह दूसरों की खुशी के लिए भी किया जाना चाहिए। श्री नारायण गुरु की जयंती है, जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम और करुणा का संदेश दिया। चंद्रशेखर ने ओणम पर्व के अवसर पर लोगों से अपील की कि जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एकता का संदेश फैलाएं। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा, आइए, जाति और धर्म के भेदभाव से परे एकता का संदेश फैलाने वाले गुरुदेव की स्मृति में अच्छाई के इस ओणम पर्व का समापन करें। गुरुदेव की शिक्षाएं सदैव हमारे मन को प्रकाशित करती रहें। भाजपा के वरिष्ठ नेता पी. मुरलीधर राव ने भी श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे सामाजिक न्याय के एक सच्चे प्रणेता थे जिन्होंने जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध निडरता से संघर्ष किया। उन्होंने पोस्ट किया, महान दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर नमन। सामाजिक न्याय के एक सच्चे समर्थक, श्री नारायण गुरु ने जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध निडरता से संघर्ष किया और सामाजिक समानता, सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं।

मंत्री सिरसा ने की दिल्ली में मुफ्त राशन वितरण की समीक्षा

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन वितरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ने बताया कि एनएफएसए के अंतर्गत सितंबर महीने का राशन लाभार्थियों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत पात्र प्रवासी लाभार्थी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि आज तक सितंबर के राशन कोटे का करीब 57 फीसद वितरित हो चुका है, साथ ही ओएनओआरसी के तहत अभी तक सितंबर माह में 1,45,610 प्रवासी लाभार्थियों ने अपना राशन प्राप्त किया है। मानसून के मौसम में भी राशन वितरण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 72,77,975 एनएफएसए लाभार्थियों को राशन वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल और चीनी उपलब्ध कराता रहा है, जिसमें प्राथमिकता वाले परिवार (पीआर/पीआरएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणियां भारत सरकार के आवंटन के अनुसार शामिल हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उचित मूल्य की दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्ड के जरिए अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित की जाए, जिसमें सतर्कता कमेटी के विवरण, श्रेणी-वार पात्रताएं, स्टॉक की स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, हेल्पलाइन नंबर और अन्य शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री सिरसा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि ओएनओआरसी योजना के तहत पात्रता की जानकारी प्रमुखता से दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई ओएनओआरसी योजना के तहत मुफ्त राशन का सुचारू और व्यवस्थित वितरण होने से दिल्ली देश में एक मिसाल बन गया है। यह योजना के अंतर्गत प्रवासियों को राशन वितरण में शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्यों में से एक है। सिरसा ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राशन बिना किसी देरी के जरूरतमंदों तक पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फेयर प्राइस शॉप्स का संचालन जारी रखें और किसी को भी राशन से वंचित न होने दें। राजस्व विभाग के साथ समन्वय से जरूरतमंदों को तैयार भोजन के पैकेट भी दिल्ली सरकार उपलब्ध करा रही हैं। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार के समन्वित प्रयास चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में नागरिकों को सहायता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। हमारे पास भोजन को जरूरत के अनुसार पहुंचाने के लिए प्रयास व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

माइग्रेन में क्या खाएं और किन चीजों से करें परहेज, एक्सपर्ट से जानें

माइग्रेन की समस्या आजकल बहुत आम होती जा रही है. इस दौरान सिर में बहुत तेज दर्द होता है. इसके साथ ही उल्टी महसूस होना और धुंधला दिखने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. इसे कंट्रोल करने के लिए डाइट पर ध्यान देना और कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं एक्सपर्ट से माइग्रेन में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं

आज के समय में लाइफस्टाइल से जुड़ी कई समस्या बहुत आम होती जा रही हैं. इसमें माइग्रेन भी शामिल है. आपने भी बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा की उन्हें माइग्रेन की समस्या है. जिसमें उनके सिर में दर्द रहता है. इसके अलावा उल्टी आना महसूस होती है, इसके अलावा रोशनी और आवाज की परेशानी होने लगती है. कई बार यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि दर्द को कम करने के लिए दवा या इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है. इसलिए इसे बचाव करने के लिए एक्सपर्ट द्वारा कई बातों को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है.

इस समस्या के दौरान सही लाइफस्टाइल और डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि कुछ फूड्स माइग्रेन के दर्द को ट्रिगर करने का काम करते हैं. इसलिए अगर आपके घर में या आपको माइग्रेन की समस्या है तो जानें एक्सपर्ट से कि आपको अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए.क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल कंसल्टेंट, न्यूरोलॉजी डॉक्टर संध्या कोचे ने बताया कि माइग्रेन की समस्या में सिरदर्द होता है, जो अक्सर सिर के एक तरफ महसूस होता है और बहुत तेज होता है. इसके साथ मरीज को मतली, उल्टी और तेज रोशनी या आवाज से परेशानी होती है. इसके कारण व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है क्योंकि दर्द इतना तेज होता है कि इसके कारण काम करना और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है. यह दर्द कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक भी रह सकता है. इसमें दूसरे लक्षणों में आंखों के सामने चमकती रोशनी या धुंधले दृश्य, और कभी-कभी हाथ-पैर में सुन्नपन या कमजोरी भी शामिल हो सकता है. आमतौर पर यह स्ट्रेस, नींद न पूरी होना, गलत खानपान या हार्मोनल बदलाव के कारण होता है. इससे बचाव के लिए जीवनशैली में सुधार, बैलेंस डाइट, नींद पूरी करना और स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है.

माइग्रेन में कौन से फूड्स खाने चाहिए और कौन से नहीं?

माइग्रेन के दौरान अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि कुछ फूड्स माइग्रेन को बढ़ावा दे सकते हैं जबकि कुछ पोषक तत्व माइग्रेन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. माइग्रेन वाले लोगों को हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, नट्स का सेवन करना चाहिए और सही मात्रा में पानी पीना चाहिए. इन फूड्स से शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो ब्रेन और शरीर की हेल्दी रखने के लिए जरूरी होते हैं. हरी सब्जियां और फल पाचन सुधरने के साथ-साथ ब्रेन को शांत रखने में मदद करते हैं और माइग्रेन के दर्द को कम करने में मददगार होते हैं. साबुत अनाज एनर्जी देते हैं, जिससे ब्लड शुगर स्थिर रहता है और सिरदर्द की संभावना कम होती है.माइग्रेन के दौरान कुछ फूड्स का सेवन करने से परहेज करना जरूरी होता है जैसे चॉकलेट, क्योंकि इसमें विटामिन होता है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है. कैफीन, ज्यादा मीठा, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा नमक का सेवन भी माइग्रेन की समस्या को बढ़ा सकता है.

एससीओ सम्मेलन:चीन ने अमेरिका को दिखाई ताकत

चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 20 से अधिक विश्व नेताओं को आमंत्रित कर बंदरगाह शहर तियानजिन में शानदार प्रदर्शन किया

तियानजिन में सार्वजनिक सौहार्द्र के प्रदर्शन के बावजूद एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के सामंजस्य को लेकर प्रमुख मतभेद हैं। कुछ सदस्य देश मामूली झड़पों, व्यापार बाधाओं या असंतुलन, प्रमुख शक्तियों के साथ समीकरणों और आतंकवाद का मुकाबला करने या संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जैसे मुद्दों पर दोहरे मानकों के साथ एससीओ में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इनमें से कुछ मुद्दों का जिक्र किया।चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 20 से अधिक विश्व नेताओं को आमंत्रित कर बंदरगाह शहर तियानजिन में शानदार प्रदर्शन किया।

यह चीन की संयुक्त मोर्चा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अमेरिका के खिलाफ एक सुरक्षित एन्क्लेव तथा बचाव का निर्माण करे और एशिया व विश्व में उससे आगे अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दे जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रतीकात्मक विचार फेनफा यूवेई (कुछ हासिल करें) के अनुरूप हो।सम्मेलन के प्रतिभागियों ने भी तियानजिन से बहुत कुछ पाया है। उदाहरण के लिए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी संघर्ष व अमेरिका तथा यूरोप के रूस के खिलाफ प्रतिबंध जैसे अत्यधिक दबाव को सह लिया है। एससीओ सभा रूस की शर्तों पर वैश्विक अलगाव को दूर करने के तरीके प्रदान करती है।

तियानजिन शिखर सम्मेलन में मोदी-पुतिन-शी की तस्वीर अमेरिका के भारत के प्रति लगातार बढ़ते अपमान और शुल्क का कड़ा जवाब है। इसके अलावा मोदी न केवल पश्चिम को रणनीतिक स्वायत्तता के संकेत भेजने में सक्षम थे बल्कि जून 2020 में गलवान में खूनी संघर्ष के बाद असहज हो गए चीन-भारत के संबंधों में स्थिरता लाने में भी सक्षम रहे।भारत एससीओ में 2005 में पर्यवेक्षक बना था। उसने 2014 में पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया और अंतत- 37 करारों पर हस्ताक्षर करने के बाद 2017 में पूर्ण सदस्य बना। वर्ष 2023 में भारत एससीओ शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भी बना। उस समय भारत ने एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की एक आभासी बैठक आयोजित की थी।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत ने आधिकारिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही स्टार्ट-अप, नवाचार, बौद्ध धर्म जैसे अन्य क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करके एक अलग एजेंडा पेश किया। इस एजेंडा को मोदी ने तियानजिन शिखर बैठक में भी दोहराया।तियानजिन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के अधिकांश प्रतिभागियों के लिए अपनी एकजुटता और पुनर्समायोजन का संकेत दिया है जो विशेष रूप से अब वैश्विक और क्षेत्रीय प्रणाली की लगातार बदलती स्थिति को दर्शाती है। बैंड वैगनिंग, यूरेशियन एकीकरण, उनकी ढांचागत और अन्य जरूरतों के लिए वित्त विकल्प हासिल करना व पड़ोसी देशों में व्यापक स्थिरता के मौकों ने रुचि पैदा की है।उदाहरण के लिए तियानजिन शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। चीन ने ऋण में 10 अरब युआन के अलावा सदस्य देशों को 28 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा की। ब्रिक्स नव विकास बैंक की तरह ही इससे न केवल क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान करने की उम्मीद है बल्कि सदस्य राज्यों की पश्चिम तथा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को भी काफी हद तक कम करने की उम्मीद है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम और संस्थान के तहत आने वाली मौद्रिक प्रणाली ग्लोबल साउथ देशों की बढ़ती आवश्यकताओं और ढांचागत जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रही है। ऐसा तब है जब कई चीनी-वित्त पोषित परियोजनाएं कर्ज के जाल में फांसने के विवाद में घिर गई हैं।

एससीओ प्रोफाइल अपने आप में प्रभावशाली है। 1996 में केवल पांच देश इसका हिस्सा थे लेकिन 2001 के बाद से यह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया को कवर करते हुए सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया है।एससीओ वर्तमान में 10 सदस्य देशों, 2 पर्यवेक्षक राज्यों और 14 संवाद भागीदारों तक विस्तारित हो गया है। इसमें वैश्विक आबादी का लगभग 44 प्रतिशत और दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई (लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर) शामिल है।

एससीओ को सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय विवाद समाधान और असैन्यीकरण के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक में समझौतों और विश्वास निर्माण उपायों की घोषणा की गई और सीमाओं को समेकित किया गया। ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान के बीच अंतर-राज्य संघर्ष जैसी कुछ घटनाओं के बावजूद यूरेशियन क्षेत्र शांति प्रदर्शित करता है।

आतंकवाद का मुकाबला करने पर एससीओ का ध्यान है और वह क्षेत्रीय विषयों पर भी नजर रख रहा है। इसने 2002 में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (आरएटीएस) की स्थापना की जिसका मुख्यालय 2022 तक ताशकंद में था लेकिन अब मास्को में स्थानांतरित हो गया। भले ही आतंकी संगठनों से निपटने के बारे में गंभीर विरोधाभास व दोहरे मानदंड मौजूद हों लेकिन आरएटीएस आतंकवादियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अर्धसैनिक अभ्यासों से संबंधित डेटा एकत्र करने में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभर रहा है।एससीओ सदस्य देशों की भागीदारी, डेटा बेस, आतंकवादी समूहों के खिलाफ जानकारी साझा करने, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी एवं अन्य मामलों के साथ शांति मिशन अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों का आयोजन धीरे-धीरे इसे एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है।

1998 में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान जब रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख किया था उस समय से ही एससीओ अमेरिका की एकतरफा नीतियों का दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है। 2005 में अपनी शिखर बैठक में एससीओ ने कहा था कि अमेरिका मध्य एशिया से सैनिकों को वापस लेने के लिए एक समय सारिणी बनाए।अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की मौजूदगी और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद यूरेशियन क्षेत्र काफी हद तक अमेरिकी प्रभाव की सीमा से बाहर रहा। ट्रम्प प्रशासन द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ चर्चा व मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया के अतिरिक्त कार्यों के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर की नियुक्ति यूरेशियन क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास हैं।भले ही ट्रम्प प्रशासन ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे कनेक्शनों को, विशेष रूप से भारत से जुड़े कनेक्शन को निशाना बना रहा है। इसके बावजूद 2013 में स्थापित एससीओ एनर्जी क्लब,ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों (रूस, कजाकिस्तान, ईरान व कुछ अन्य) तथा ऊर्जा उपभोक्ताओं (चीन, भारत एवं अन्य) के रूप में एक अद्वितीय और उपयोगी संयोजन प्रदान करता है।तियानजिन में सार्वजनिक सौहार्द्र के प्रदर्शन के बावजूद एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के सामंजस्य को लेकर प्रमुख मतभेद हैं। कुछ सदस्य देश मामूली झड़पों, व्यापार बाधाओं या असंतुलन, प्रमुख शक्तियों के साथ समीकरणों और आतंकवाद का मुकाबला करने या संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जैसे मुद्दों पर दोहरे मानकों के साथ एससीओ में प्रवेश कर रहे हैं।

संपादकीय

शांति की ओर मणिपुर

निस्संदेह, पिछले दो वर्ष से अधिक समय से हिंसाग्रस्त मणिपुर का संकट लाइलाज-सा नजर आता रहा है। अब केंद्र सरकार और राज्य के दो प्रमुख कुकी-जो समूहों के बीच बीते गुरुवार को हस्ताक्षरित ऑपरेशन निलंबन समझौते से अशांत मणिपुर में शांति बहाली तथा सामान्य स्थिति बनाये रखने के प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद जगी है। उम्मीद है कि इस प्रयास से राज्य की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित की जा सकेगी। समझौते के बाद निर्दिष्ट शिविरों को संवेदनशील क्षेत्रों से स्थानांतरित करने और राज्य में दीर्घकालिक शांति तथा स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में भी सहमति बनी है। वहीं यह घटनाक्रम इस कारण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह इस पूर्वोत्तर राज्य का दौरा कर सकते हैं। विपक्ष लंबे समय से मांग करता रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। मई, 2023 में मैतेई और कूकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री की इस संवेदनशील राज्य की यह पहली यात्रा होगी। विगत में विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया। विपक्ष ने राज्य में डबल इंजन सरकार के दौरान कुशासन का आरोप भी लगातार लगाया है। उनका यह भी आरोप रहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य की स्थिति के नियंत्रण में अपनी विफलता के बावजूद एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री के पद पर बनाये रखा था। इससे बढ़कर यह भी कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन पर तटस्थता न दिखाने और हिंसा के प्रति संवेदनहीन बने रहने के आरोप भी लगाए गए। कालांतर विपक्ष के दबाव के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से लेकर अब तक राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत संचालित है। वहीं हाल के महीनों में अपेक्षाकृत शांति का एक मुख्य कारण यह भी है कि कई आतंकवादियों ने राज्य के अधिकारियों की अपील के जवाब में लूटे गए हथियार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लौटाए हैं।

निश्चित रूप से हाल ही में हुआ समझौता लंबे समय से अशांत चल रहे मणिपुर के हित में एक स्वागत योग्य कदम ही कहा जाएगा। इसके बावजूद कुछ पेचीदा मुद्दे अभी भी सुलझाने बाकी हैं। इस मुहिम में विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की जरूरत है। राज्य में एक प्रभावशाली नागरिक समाज समूह, कुकी-जो काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि वह मैतेई और कुकी-जो क्षेत्रों के बीच बफर जोन में अप्रतिबंधित या मुक्त आवाजाही के पक्ष में नहीं। यह भी कि मणिपुर के नागाओं के शीर्ष निकाय ने मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया है। इसके अलावा विरोध में राज्य में समुदाय वाले सभी क्षेत्रों में व्यापार प्रतिबंध लागू करने की चेतावनी भी दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में जातीय संघर्ष की मूल वजह बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल करने की मांग रही है। इस मांग पर उपजे टकराव को दूर करने तथा कुकी और नागाओं का विश्वास फिर से हासिल करने के प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है। निश्चय ही, सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने के लिये मोदी सरकार को अब समय नहीं गवांना चाहिए। निस्संदेह, मणिपुरियों ने पहले ही इस राहत के लिये बहुत लंबा इंतजार किया है। यह अच्छी बात है कि कूकी-जो काउंसिल ने अलग से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को खोलने का फैसला लिया है। यह राजमार्ग मणिपुर से होकर गुजरता है। निस्संदेह, इस कदम से जहां राज्य में जीवन की जरूरी चीजों की आपूर्ति सरल होगी, वहीं विस्थापित परिवारों और राहत शिविरों में हालात के चलते रह रहे नागरिकों की मुश्किलें कम हो सकेंगी। वहीं पिछले कुछ महीनों से राज्य में जारी शांति की स्थिति को स्थायी बनाने की दिशा में शासन-प्रशासन की ओर से गंभीर प्रयासों की जरूरत है। सुखद यह भी है कि समझौते में कूकी संगठनों ने अपने शिविरों की संख्या कम करने तथा हथियारों को निकटवर्ती बीएसएफ और सीआरपीएफ शिविरों में पहुंचाने पर भी सहमति जतायी है।

नेताओं को सुधारने के लिए बन रहे हैं इंडोनेशिया जैसे हालात

इंडोनेशिया की राजधानी में संसद पहुंचने की कोशिश कर रहे हजारों पत्थरबाज छात्रों पर दंगा पुलिस ने आंसू गैस के कई राउंड दागे। ये छात्र संसद सदस्यों के भव्य भत्तों का विरोध करने के लिए वहां पहुंचे थे। प्रदर्शनकारी हाल की रिपोर्टों से नाराज थे कि प्रतिनिधि सभा के 580 सदस्यों को सितंबर 2024 से प्रति माह 50 मिलियन रुपिया (एसडी 3,075) का आवास भत्ता मिल रहा है। सांसदों को प्रति महीने दिया जाने वाला भत्ता एक इंडोनेशियाई नागरिक के प्रति महीने आय से 20 गुना ज्यादा है। इंडोनेशिया की संसद के 580 सदस्यों को सितंबर 2024 से 5 करोड़ रुपये (3,075 डॉलर) आवास भत्ता के तौर पर दिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि 28 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश में पुलिस और संसद सदस्यों को व्यापक रूप से भ्रष्ट माना जाता है। नेताओं के रवैये को देखकर लगता है कि भारत में भी देर-सबेर ऐसे हालात बन रहे हैं। मंत्री, सांसद-विधायकों का सही मायने में देश के लोगों की हालत से ज्यादा सरोकार नहीं रह गया है। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे तय थे किन्तु 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। हंगामें के कारण कार्रवाई ठप होने से जनता कई सौ करोड़ के धन का नुकसान हुआ। लगातार व्यवधानों के कारण केवल एक तिहाई समय तक ही सक्रिय रूप से चल पाया। इसमें बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का रहा। अधिकांश समय हंगामे में बीता, जिससे विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किए गए। राज्य सभा में 285 सवाल पूछने के बावजूद केवल 14 सवालों का ही जवाब सत्र के दौरान दिया गया। लगातार 20 दिनों तक इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण केमुद्दे पर लोक सभा और राज्य सभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही काफी बाधित हुई। राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अपने समापन भाषण में कहा कि कुल मिलाकर, सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चल पाया। इस सत्र की उत्पादकता निराशाजनक रूप से सिर्फ 38.88 प्रतिशत रही, जो गंभीर आत्मचिंतन का विषय है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुने हुए जनप्रतिनिधी देशहित के लिए कितने गंभीर हैं।

काम नहीं तो वेतन नहीं, संसद में इस मुद्दे पर कोई आवाज नहीं उठाता। किसी भी कारण से संसद का कामकाज हो या नहीं, इससे सांसदों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पूरा वेतन-भत्ता मिलता है। काम नहीं करने के आधार पर इसमें कटौती की कोई चर्चा तक नहीं करता। दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल अकेले ऐसे सांसद रहे जिन्होंने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा था कि अगर सदन नहीं चलता है, तो सांसदों को भत्ता भी नहीं मिलना चाहिए। उनका दावा था कि सांसदों को भत्ता तो मिलता है, लेकिन जनता के काम नहीं हो पाते। उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्ता और विपक्ष दोनों की इगो के कारण सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, जबकि विपक्षी दल सरकार को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में कार्य नहीं होने पर सांसदों का वेतन और अन्य लाभ रोके जाने चाहिए। संसद की कार्रवाई ठप करने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोपों का ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन जब बात वेतन-भत्ते बढ़ाने की आती है तो सब मिल कर एक हो जाते हैं। इस पर कोई बहस तक नहीं होती। वेतन-भत्तों के एवज में सांसदों की उत्पादकता कितनी रही, इसका विश्लेषण तक नहीं किया जाता। देश जब 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तब उस दौरान मॉनसून सत्र में 79 घंटे भी संसद नहीं चली। देश की संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में 83 घंटे काम नहीं हुआ। इससे 124 करोड़ 50 लाख रुपए जनता का धन बर्बाद हुआ। राज्यसभा में 73 घंटे ठप रही, इससे 80 करोड़ रुपए व्यर्थ गए। मतलब दोनों सदनों में मिलाकर 204 करोड़ 50 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। संसद में जहां घंटाभर बैठकर सांसद काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही 5-5 साल की जिम्मेदारी देकर जनता भेज देती है। संसद में बैठने वाले 93 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, जिन्हें अभी एक लाख 24 हजार रुपए हर महीने वेतन मिलता है। संसदीय क्षेत्र भत्ता 84 हजार रुपए होता है। दैनिक भत्ता सांसदों का 2500 रुपए है। वेतन भत्ता जोड़कर हर सांसद को हर महीने दो लाख 54 हजार रुपए जनता के पैसे से दिया जाता है। देशहित के नाम पर हंगामा कर संसद की कार्रवाई ठप करने में सांसद कोई मौका नहीं छोड़ते पर जब बात वेतन-भत्ते बढ़ाने की आती है तो सब एक हो जाते हैं। गत वर्ष संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। नया वेतन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी माना गया। इसके साथ ही सांसदों का मासिक वेतन कुछ भत्तों और सुविधाओं के अलावा 1.24 लाख रुपये हो गया है। सरकार का कहना था कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई। वहीं पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गयी। इसमें कहा गया है कि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई। 1954 के सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत उन्हें यह सुविधा दी गई है। हर पांच साल में होता है रिव्यू 2018 के बाद से सांसदों के वेतन और भत्ते की हर पांच साल पर समीक्षा होती है। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों के लिए कानून में संशोधन किया गया था। सांसदों को विट्ठलभाई पटेल (वीपी) हाउस में हॉस्टल से लेकर मध्य दिल्ली में दो बेडरूम वाले फ्लैट और बंगले तक आवास मिलता है। उन्हें बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क के लिए भी राशि दी जाती है। संसद में निरंतर हंगामे के परिणामस्वरूप दोनों सदनों में लंबे समय तक स्थगन होता है जो अंतत- सदन में सार्वजनिक नीति के निर्माण को प्रभावित करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, जहां नीति पर अपनी राय के साथ हर किसी की अपनी आवाज है, लेकिन ये लंबे समय तक व्यवधान संसद की क्षमता को कम कर रहा है। दिन के अंत में हमें क्या परिणाम मिलता है, और चर्चा से हमें कितना लाभ होता है? संसद अपने नियम और विनियम बनाती है, विधायी निकायों के प्रभावी कामकाज के लिए उन नियमों और विनियमों का पालन करना सदस्यों पर निर्भर है। ऐसा कब तक होगा? संसद को व्यक्तिगत स्तर और पार्टी स्तर दोनों पर आंतरिक जांच और संतुलन के साथ आना होगा। बार-बार व्यवधान डालने पर आनुपातिक दंड लगाया जा सकता है। एक संसद व्यवधान सूचकांक तैयार किया जा सकता है जिस पर व्यवधानों का स्वत- निलंबन लागू किया जा सकता है। साथ ही संसद के कार्य दिवसों में वृद्धि की जानी चाहिए। लगातार व्यवधान एक नया मानदंड बनता जा रहा है जो पार्टियों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ाता है।

डियाजियो का भारत में अपने कारोबार में विस्तार का इरादा

एजेंसी

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनियों में से एक ब्रिटेन की 'डियाजियो' कंपनी धीरे-धीरे भारत में अपना विस्तार कर रही है।कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि डियाजियो भारत में अपनी सहायक इकाई 'डियाजियो इंडिया' के माध्यम से कारोबार रही है और भविष्य में इसका अपने बिजनेस में विस्तार करने का इरादा है। गौरतलब है कि यह कंपनी दुनिया के 180 देशों में कारोबार कर रही है और इसने पिछले वर्ष 27 अरब डॉलर का कारोबार किया था। कंपनी भारत में तेजी से अपना विस्तार कर रही है। डियाजियो के कई फेमस ब्रांड में मैक डॉवेल्स, रॉयल चैलेंज जॉनी वॉकर सिग्नेचर, ब्लैकडॉग, ब्लैक एंड वाइट आदि हैं।कंपनी ने हाल में रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड, जॉनी वॉकर ब्लॉन्ड जैसे ब्रांड्स लॉन्च किए और कई छोटी कंपनियों को भी खरीदा है।कंपनी ने शनिवार को गुरूग्राम में रॉयल चैलेंज अमेरिकन प्राइड 'रोडियो नाइट्स' की शुरुआत की और शहर के युवाओं में जोश भर दिया। अमेरिकाना और वाइल्ड वेस्ट की भावना से प्रेरित इस कार्यक्रम में संगीत, गेम्स और नृत्य जबरदस्त संगम देखने को मिला। गुरुग्राम के सोका में आयोजित इस कार्यक्रम को खासतौर पर युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था।

एफपीआई ने पहले सप्ताह निकाले 9,431 करोड़ रुपये

मुंबई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 9,431 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। केंद्रीय डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने बीते सप्ताह इक्विटी में 12,257 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। डेट को छोड़कर अन्य सभी सेगमेंट में वे बिकवाल रहे। डेट में उन्होंने 3,534 करोड़ रुपये लगाये। आलोच्य सप्ताह में म्यूचुअल फंड में एफपीआई निवेश 742 करोड़ रुपये घट गया। वहीं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने 42.38 करोड़ रुपये की निकासी की। यह लगातार चौथा महीना है जब एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त में उन्होंने 20,635 करोड़ रुपये, जुलाई में 5,261 करोड़ रुपये और जून में 7,769 करोड़ रुपये निकाले थे। इस साल मार्च और मई को छोड़कर शेष सभी महीने वे बिकवाल रहे हैं। पूरे कैलेंडर वर्ष में उनकी शुद्ध निकासी 51,471 करोड़ रुपये रही थी।

गेहूं-चावल नरम; खाद्य तेलों में घटबढ़, चीनी और दालें भी सस्ती

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह मंदी रही। चावल के औसत भाव गिर गये। गेहूं में भी गिरावट रही। खाद्य तेलों में घटबढ़ देखी गयी जबकि चीनी और दालों में साप्ताहिक नरमी का रुख रहा। घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 51 रुपये कम होकर सप्ताहांत पर 3,776.83 रुपये प्रति क्विंटल पर रही। वहीं, गेहूं करीब सात रुपये सस्ता होकर 2,848.96 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटे की कीमत कमोबेश स्थिर रही और सप्ताहांत पर यह 3,312.11 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। सरसों तेल की औसत कीमत 63 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। मूंगफली तेल में करीब 147 रुपये और वनस्पति में 151 रुपये प्रति क्विंटल की साप्ताहिक मंदी रही। सोयाबीन तेल 44 रुपये और सूरजमखी तेल 62 रुपये सस्ता हुआ। वहीं, पाम ऑयल 47 रुपये प्रति क्विंटल टूट गया। बीते सप्ताह दाल-दलहनों के दाम घट गये। चना दाल औसतन करीब 67 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी। उड़द दाल में 30 रुपये और दाल मूंग में 52 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी देखी गयी। तुअर दाल भी 113 रुपये उतर गयी। मसूर दाल में 17 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट रही। गुड़-चीनी : मीठे के बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह नरमी देखी गयी। गुड़ के औसत भाव 19 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी के नौ रुपये प्रति क्विंटल टूट गये।

इंडियन बैंक सुरक्षित वेब पोर्टल पर स्थानांतरित हुआ

चेन्नई। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट का डोमेन बदलकर 'इंडियन बैंक डॉट बैंक डॉट इन' कर दिया है। पूरी कवायद का मकसद धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय करना और डिजिटल बैंकिंग समाधानों में जनता का भरोसा बढ़ाना है। चेन्नई स्थित इस बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के तहत यह पहल की है, जो इस डोमेन का विशेष रजिस्ट्रार है। बैंक ने एक बयान में कहा, 'बैंक डॉट इन' डोमेन विशेष रूप से बैंकों के लिए आरक्षित है और धोखाधड़ी से निपटने, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाने और ग्राहकों को वास्तविक बैंकिंग वेबसाइटों की पहचान करने में मदद करता है। बयान में कहा गया कि बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए वेबसाइट को एक सुरक्षित डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया है।

स्टॉक मार्केट में रचित प्रिंट्स की बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत, कमजोर लिस्टिंग के बाद और लुढ़का शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली । मैट्रेस इंडस्ट्री के लिए खास तरह के फैब्रिक तैयार करने वाली कंपनी रचित प्रिंट्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को काफी निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 149 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 119.20 रुपये के स्तर पर हुई। कमजोर लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कंपनी के शेयरों के भाव में और गिरावट आ गई। पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे कंपनी के शेयर 114 रुपये के स्तर पर बने हुए थे। इस तरह अभी तक के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 23.49 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। रचित प्रिंट्स का 19.50 करोड़ रुपये का आईपीओ 1 से 3 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.97 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.01 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.25 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.74 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 13.09 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी प्लांट और मशीनरी की खरीदारी करने, पुराने कर्ज को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 32 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 2.03 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 4.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 12 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 41.78 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

भारत, इजराइल इस हफ्ते द्विपक्षीय निवेश संधि पर कर सकते हैं हस्ताक्षर

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत और इजराइल एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये समझौता इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच की इस हफ्ते होने वाली भारत यात्रा के दौरान हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने दी जानकारी में बताया कि इस हफ्ते इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान

भारत और इजराइल आपस में एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की नींव भी रख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बेजेल स्मोट्रिच इस हफ्ते 8 से 10 सितंबर तक भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, इजराइली वित्त मंत्री मुंबई और गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का भी दौरा करेंगे।

ऑडी ने 7.8 लाख रुपये तक घटाये वाहनों के दाम, नई कीमतें 22 सितंबर से होगीं लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया ने सोमवार को भारत में अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 2.6 लाख रुपये से लेकर 7.8 लाख रुपये तक कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होगीं। ऑडी इंडिया ने एक बयान में कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद उसने अपने सभी उत्पाद पोर्टफोलियो की कीमतों में संशोधन किया है, ताकि ऑटोमोबाइल पर जीएसटी कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके। अब ग्राहकों को मॉडल के आधार पर 2.6 लाख रुपये से लेकर 7.8 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। कंपनी के मुताबिक नई कीमतों के तहत कंपनी की एंट्री-लेवल एसयूवी क्यू3 की शुरुआती कीमत 43.07 लाख रुपये हो जाएगी, जो पहले 46.14 लाख रुपये थी। इसी तरह टॉप-एंड एसयूवी क?यू8 की शुरुआती कीमत 1.18 करोड़ रुपये से घटकर अब 1.1 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसके अलावा एसयूवी क्यू5 और क्यू7 जैसे अन्य मॉडलों के साथ-साथ सेडान ए4 और ए6 की कीमतों में भी कमी की गई है। कंपनी ने कहा कि संशोधित कीमतें लागू होने के बाद ऑडी की लक्जरी कारों और एसयूवी रेंज को और अधिक सुलभ बनाएगी, जिससे त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों की मांग में तेजी आएगी। ग्राहक अपनी पसंदीदा कार की सटीक कीमत जानने के लिए ऑडी इंडिया के नजदीकी डीलरशिप पर जा सकते हैं या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

अगस्त में सुस्त रही वाहनों की खुदरा बिक्री

एजेंसी

नई दिल्ली। त्योहारी मौसम और जीएसटी में राहत के इंतजार में अगस्त में ग्राहकों ने अपनी खरीद टाल दी जिससे वाहनों की खुदरा बिक्री में सुस्ती देखी गयी।

वाहन डीलरों के महासंघ (फाडा) के सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि अगस्त में यात्री वाहनों (कार, एसयूवी और वैन) की बिक्री अगस्त 2024 के मुकाबले मात्र 0.93 प्रतिशत बढ़ी और कुल बिक्री 3,23,256 इकाई रही। दुपहिया वाहनों में भी 2.18 फीसदी की मामूली तेजी देखी गयी और कुल 13,73,775 वाहन बिके। वाहनों की कुल बिक्री 2.84 फीसदी बढ़कर 19,64,547 इकाई रही।

फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विघ्नेश्वर बताया कि 15 अगस्त को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी खरीद टाल दी। हालांकि डीलरों के पास पूछताछ काफी आयी, लेकिन वह बिक्री में पूरी तरह से नहीं बदल सकी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि 22 सितंबर को जीएसटी सुधारों के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ग्राहक खरीद करेंगे। अगस्त में तिपहिया वाहनों की बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 2.26 प्रतिशत घट गयी। वहीं, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 8.55 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गयी। अच्छे मानसून के कारण ट्रैक्टरों की बिक्री में 30.14 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल आया।

फाडा का कहना है कि निकट भविष्य में सितंबर में त्योहारी मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। अच्छी विकास दर, कम मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता मांग को गति प्रदान कर रही है। उसने बताया कि जीएसटी सुधार वाहन उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होंगे।

उसने कहा कि सितंबर में दो तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जीएसटी सुधारों के लागू होने से पहले खरीद में सुस्ती रहेगी जबकि 22 सितंबर से इसमें जबरदस्त तेजी आयेगी।

सर्राफा बाजार में नई ऊंचाई पर सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज तेजी का रुख बना हुआ है। आज की तेजी के कारण सोना ने आज एक बार फिर मजबूती के नए शिखर पर अपनी जगह बना ली है। बाजार में आई तेजी के कारण 24 कैरेट सोना 1.08 लाख रुपये के स्तर को पार कर गया है, वहीं 22 कैरेट सोना 1 लाख रुपये के स्तर के काफी करीब पहुंच गया है। सोने की तरह ही चांदी भी आज 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगा हो गया है।कीमत में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज प्रति 10 ग्राम 1,08,460 रुपये से लेकर 1,08,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 99,350 रुपये से लेकर 99,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी उछाल आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,08,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 99,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,08,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 99,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,08,510 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,08,460 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 99,350 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,08,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 99,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,08,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 99,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,08,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 99,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

इजराइली वित्त मंत्री स्मोट्रिच की भारत यात्रा, आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा

एजेंसी

नई दिल्ली। इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है। श्री स्मोट्रिच अपने भारतीय समकक्ष और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे।

द्विपक्षीय निवेश संधि पर होगी बात

इस यात्रा का एक प्रमुख एजेंडा दोनों देशों के बीच लंबित द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है। यह संधि दोनों देशों के निवेशकों को एक सुरक्षित और स्थिर कानूनी ढांचा प्रदान करेगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोनों ही पक्ष इस संधि पर जल्द हस्ताक्षर करने को लेकर उत्साहित हैं।

तकनीक और व्यापार में सहयोग

स्मोट्रिच की इस यात्रा के दौरान केवल निवेश ही नहीं, बल्कि तकनीक, रक्षा, कृषि और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत ने निर्यात उपायों के दुरुपयोग पर आगाह किया

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने एससीओ बैठक में निर्यात संबंधी उपायों को हथियार बनाने या उनका दुरुपयोग करके कृत्रिम कमी पैदा करने, बाजार को बिगाड़ने या आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने के प्रति आगाह किया है। वाणिज्?य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि भारत ने छह सितंबर को व्लादिवोस्तोक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के व्यापार मंत्रियों की बैठक में कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में भरोसा बनाए रखने के लिए इन कदमों का संतुलित और पारदर्शी उपयोग जरूरी है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अमिताभ कुमार ने बैठक में विश्व व्यापार संगठन (डबल्यूटीओ) को केंद्र में रखते हुए एक खुली, निष्पक्ष, समावेशी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने यह भी कहा कि व्यापार से जुड़े जलवायु उपायों के चलते अनुचित भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित करके और व्यापार सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाकर लगातार व्यापार घाटे को दूर करने का भी आह्वान किया। ये टिप्पणियां इसलिए अहम हैं, क्योंकि भारत के वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को चीन के दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक और उर्वरक पर निर्यात प्रतिबंधों के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चीन भी इस संगठन का सदस्य है।

एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत ने निर्यात उपायों के दुरुपयोग पर आगाह किया।

हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्द्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया, पांच जनवरी को संभालेंगे कार्यभार

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वे 5 जनवरी 2026 को अपना पदभार संभालेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद हर्षवर्धन चितले को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। चितले के पास पिछले 3 दशकों से अधिक समय तक वैश्विक नेतृत्व करने का अनुभव है। उनका कार्यकाल 5 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। कंपनी ने बताया कि चितले के सीईओ का पद संभालने के बाद विक्रम कस्बेकर कार्यवाहक सीईओ का पद छोड़ देंगे। चितले ने सिग्निफाई के प्रकाश समाधानों के व्यवसाय के वैश्विक सीईओ के रूप में काम किया है, जहां उन्होंने 70 देशों में 12,000 कर्मचारियों का नेतृत्व किया। उनके पास औद्योगिक स्वचालन, प्रकाश व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन में गहरी विशेषज्ञता है। हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल ने एक बयान में कहा, वृद्धि को गति देने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने में हर्षवर्धन चितले का उत्कृष्ट रिकॉर्ड उन्हें इस महत्वपूर्ण क्षण में हीरो मोटोकॉर्प के लिए आदर्श नेता बनाता है। हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले की नियुक्ति ऐसे समय में की है, जब कंपनी ने अगस्त महीने में भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री में शीर्ष स्थान जापान की होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के हाथों खो दिया है।

राजस्थान सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए आरवीयूएनएल को भूमि आवंटित की

नई दिल्ली। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने जैसलमेर और बीकानेर जिलों में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) को भूमि आवंटित की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि जैसलमेर में 26,400 मेगावाट (मेगावाट) की संयुक्त क्षमता वाले विभिन्न सौर पार्कों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।इसी तरह बीकानेर में 5,200 मेगावाट क्षमता वाले सौर पार्कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। राज्य के टिकाऊ विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों के अनुरूप, ये मंजूरियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति को मजबूत करेंगी। शर्मा ने कहा कि यह पहल न केवल राजस्थान को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाएगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

साप्ताहिक शेयर समीक्षा- अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सकारात्मक संकेतों के सपोर्ट से बढ़त के साथ बंद हुआ स्टॉक मार्केट

एजेंसी

नई दिल्ली। जीएसटी सिस्टम में किए गए सुधार, घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के कारण पिछले सप्ताह के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। शुक्रवार 05 सितंबर को खत्म हुए कारोबारी सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 901.11 अंक यानी 1.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 80,710.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी ने 314.15 अंक यानी 1.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,741 अंक के स्तर पर पिछले सप्ताह के कारोबार का अंत किया। बीएसई का लार्ज कैप इंडेक्स पिछले सप्ताह के कारोबार में 1.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। इस इंडेक्स में शामिल बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्विगी, टीवीएस मोटर कंपनी, जिंदल स्टील और आयशर मोटर्स के शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए। इसी तरह बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1 सितंबर से 5 सितंबर के कारोबार के बाद 2 प्रतिशत की साप्ताहिक मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। इस इंडेक्स में शामिल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल रेल विकास निगम ब्रेनबीज सॉल्यूशंस और एनएमडीसी के शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए। पिछले सप्ताह के कारोबार में बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स सबसे अधिक 2.5 प्रतिशत की मजबूती हासिल करने में सफल रहा। इस इंडेक्स में शामिल वन मोबिक्विक सिस्टम्स, अतुल ऑटो, नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया, गुजरात मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जाइडस वेलनेस, विमता लैब्स, जय कॉर्प, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज और हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया के शेयर 20 से लेकर 39 प्रतिशत तक की साप्ताहिक मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें, तो पिछले सप्ताह के कारोबार में बीएसई का मेटल इंडेक्स 6 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहा। इसी तरह भी बीएसई का ऑटोमोबाइल इंडेक्स 5.2 प्रतिशत की साप्ताहिक मजबूती हासिल करने में सफल रहा। इसके अलावा बीएसई का कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3.6 प्रतिशत की साप्ताहिक उछाल के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर, बीएसई का आईटी इंडेक्स 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें, तो पिछले सप्ताह भी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बिकवाली जारी रखी। लगातार 10वें सप्ताह बिकवाली करते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों ने घरेलू शेयर बाजार में पूरे सप्ताह के दौरान 5,666.90 करोड़ रुपये के शेयर बेच डाले। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) लगातार 21वें सप्ताह खरीदार (बायर) की भूमिका में बने रहे। इस सप्ताह घरेलू संस्थागत निवेशकों ने स्टॉक मार्केट में कुल 13,444.09 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीदारी की।

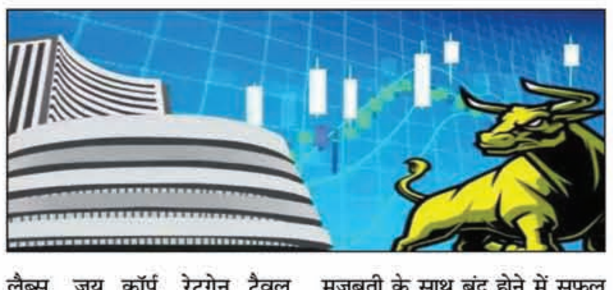

इजराइल के ऐलात स्थित रेमन एयरपोर्ट पर यमन की ओर से ड्रोन हमले में दो घायल, कुछ घंटों बाद उड़ानें फिर बहाल

एजेंसी

ऐलात। दक्षिणी इजराइल के पर्यटन शहर ऐलात के पास स्थित रेमन एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ, जब यमन से छोड़ा गया एक ड्रोन हवाई अड्डे के आगमन हॉल में आकर गिरा। इस हमले में शारपनेल लगने से दो लोग घायल हो गए। इजराइल की राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा मागन डेविड एडोम के अनुसार, घायलों में एक 63 वर्षीय पुरुष और एक 52 वर्षीय महिला शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।हमले के बाद एयरपोर्ट पर करीब दो घंटे तक उड़ान संचालन रोक दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। इजराइल एयरपोर्ट प्राधिकरण ने बताया कि सभी सुरक्षा मानकों और वायुसेना की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया है। एयरपोर्ट से जल्द ही पहली उड़ान तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। रेमन एयरपोर्ट, जो जॉर्डन और मिस्र की सीमा के पास रेड सी (लाल सागर) के तटीय शहर इलात में स्थित है, मुख्यतः घरेलू उड़ानों को संभालता है। यहां से इजराइर और आर्किया एयरलाइंस की उड़ानें निर्धारित थीं। आर्किया ने बताया कि यात्रियों और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सुरक्षा जांच के बाद कंपनी ने सामान्य संचालन बहाल करने की बात कही।

यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हवाई हमला, कीव पर दागे 800 से ज्यादा ड्रोन, कैबिनेट भवन को भी निशाना बनाया

कीव। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला करते हुए शनिवार की देर रात से रविवार सुबह तक 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागीं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। रूसी हमले में ऐसा पहली बार है कि यूक्रेन सरकार की मुख्य इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। दमकल कर्मी इन तमाम इमारतों की आग बुझाते हुए देखे गए और पूरे शहर में अफरातफरी का माहौल रहा। कीव पोस्ट के मुताबिक रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों ने 751 ड्रोनों को रोका या निष्क्रिय किया, लेकिन मिसाइलों और ड्रोनों से देशभर में 37 स्थानों पर हमले किये गए, जिससे कई जगह आग लग गई। इन हमलों में कई आवासीय एवं प्रशासनिक इमारतें नष्ट हुई हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब किसी सरकारी मुख्यालय पर हुए हमले में कैबिनेट भवन में आग लग गई। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस की तरफ से रात भर ऐसे हमलों का सिलसिला जारी रहा। हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई, जो मिसाइल हमलों में बदल गई। रूस के इन हमलों के दौरान भारी दहशत और अफरातफरी की स्थिति देखी गई।

सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस की मांग- सोशल मीडिया प्लेटफार्म बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार

काठमांडू। नेपाली कांग्रेस (एनसी) ने कई सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने के हालिया फैसले पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेता जल्द ही प्रधानमंत्री ओली से बातचीत करेंगे।नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के आवास पर हुई पार्टी की कार्य संपादन समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत की जाए। पार्टी के संयुक्त महासचिव डीना उपाध्याय के अनुसार कई नेताओं ने सरकार के इस कदम पर असंतोष व्यक्त किया। उपाध्याय ने कहा कि सोशल मीडिया का नियमन आवश्यक है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद करना सही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करने वाले हैं। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसी ने कहा कि सोशल मीडिया बंद करने के फैसले ने व्यापक रूप से जनता के असंतोष को जन्म दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब सरकार इस तरह के एकतरफा और विवादास्पद निर्णय लेती है, तो नेपाली कांग्रेस को हस्तक्षेप करना चाहिए। केसी ने इस कदम को अनुचित और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि बिना पूर्व परामर्श के संसद में विचाराधीन मुद्दे पर सरकार के इस कदम के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की भी आलोचना की।

रूसी कैंसर वैक्सीन 'उपयोग के लिए तैयार'

मास्को। कैंसर के इलाज के लिए रूस के वैज्ञानिकों की बनाई कैंसर वैक्सीन उपयोग के लिए तैयार हो गयी है। इस दवा को अब केवल रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा है। रशिया टुडे, ने यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यह वैक्सीन कैंसर के रोगियों के लिए आशा की नई किरण बन कर उभरी है। इस दवा ने अपने शुरुआती परीक्षणों में कैंसर में बनने वाली रसौली के आकार और वृद्धि को 80 फीसदी तक कम कर दिया है। रूस की फेडरल मेडिकल-बायोलॉजिकल एजेंसी की प्रमुख वेरोनिका स्कोर्तसोवा के अनुसार, इस नव-विकसित कैंसर वैक्सीन ने शुरुआती परीक्षणों में शानदार परिणाम दिया है और अब यह बाजार में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इसे रोगियों को दिया जा सकेगा।दवा विकसित करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि बीते तीन साल से इस दवा के परीक्षण किए जा रहे थे। इन परीक्षणों में काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। इसके शुरुआती उपयोग कोलोरेक्टल कैंसर के लिए किया जाएगा, इसके बाद ग्लियोब्लास्टोमा और मेलेनोमा के लिए टीके लगाए जायेंगे।

दक्षिणी चीन पहुंचा तूफान तपाह, स्कूल बंद, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया

एजेंसी

ग्वांगझोउ । इस साल का 16वां तूफान तपाह सोमवार सुबह दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पहुंच गया। इसको देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया और हजारों निवासियों को तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ग्वांगडोंग की मौसम विज्ञान वेधशाला के अनुसार, 30 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम गति वाली हवाओं के साथ तूफान सुबह लगभग 8ऱ्50 बजे जियांगमेन शहर के एक काउंटी-स्तरीय शहर ताइशान में तट पर पहुंचा। ताइशान के 182 स्कूलों और किंडरगार्टन में लगभग 1,20,000 छात्रों की कक्षाएं स्थगित कर दी गई, जबकि जियांगमेन में 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। जियांगमेन के मेरीटाइम ब्यूरो ने कहा कि उसने संभावित आपात स्थितियों से निपटने

के लिए 43 स्वयंसेवी समुद्री बचाव दल और 30 जहाज पहले ही तैनात कर दिए। ताइशान में 3,300 से ज्यादा आपातकालीन कर्मी तैयार हैं। पड़ोसी यांगजियांग शहर में अधिकारियों ने सोमवार को स्थानीय निवासियों के लिए आपातकालीन आश्रय स्थल खोल दिए। तूफान से प्रभावित ग्वांगडोंग के कुछ हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश और तेज हवाएं चलीं। समाचार एजेंसी के अनुसार, मौसम विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि तपाह लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और धीरे-धीरे कमजोर होता जाएगा। इससे पहले, हांगकांग वेधशाला ने तूफान तपाह के कारण रविवार शाम को सबसे पहले नंबर 8 का संकेत जारी किया था, जो हांगकांग की पांचस्तरीय तूफान चेतावनी प्रणाली के तहत तीसरा सबसे बड़ा अलर्ट है। हांगकांग हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सोमवार को लगभग 100 उड़ानें रद्द होने की आशंका है। तपाह के मद्देनजर मनोरंजन पार्क और क्लीनिक बंद हैं। चीन के हैनान प्रांत से आने-जाने वाली क्रॉस-सी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या उनके मार्ग बदल दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अकेले यांगजियांग शहर में रविवार सुबह 9 बजे तक 26 अपतटीय पवन ऊर्जा प्लेटफार्मों से कुल 1,785 श्रमिकों को निकाला गया था।

फेसबुक-इंस्टा बैन होने पर नेपाल में बवाल : संसद में घुसे युवा प्रदर्शनकारी, पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस छोड़ी

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन सोमवार को उग्र हो गया। हजारों की संख्या में जुटे 18 से 30 वर्ष के युवाओं ने संसद भवन का रुख किया और गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा जमा लिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन, आंसू गैस और कई राउंड फायरिंग का सहारा लिया। इस दौरान हुई झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, संसद भवन परिसर के बाहर करीब 12

हजार से अधिक प्रदर्शनकारी मौजूद थे। हालात पर काबू पाने के लिए राजधानी काठमांडू समेत आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सेना को तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ यह विरोध पहले से ही कई शहरों में चल रहा था। सुरक्षा बलों की सख्त निगरानी के बावजूद प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे। नेपाल के इतिहास में यह पहला मौका है जब संसद परिसर में युवाओं ने इस तरह की घुसपैठ की है।

शिगेरु इशिबा के इस्तीफे के बाद जापान के पूर्व विदेश मंत्री मोटेगी एलडीपी नेतृत्व की दौड़ में शामिल

एजेंसी

टोक्यो । जापान के पूर्व विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के इस्तीफे के फैसले के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष चुनाव में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने रविवार शाम को अपना पद छोड़ने का ऐलान किया था। जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनाव में हार के बाद एलडीपी-कोमेइतो गठबंधन ने अपना बहुमत खो दिया था। समाचार एजेंसी ने सोमवार को क्योडो न्यूज के हवाले से खबर दी। क्योडो न्यूज ने पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताया कि पार्टी की चुनावी हार की जिम्मेदारी लेने की बढ़ती मांग के बीच शिगेरु इशिबा ने यह कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उम्मीद है कि एलडीपी मंगलवार तक मतदान प्रक्रिया को अंतिम रूप देगी। तोशिमित्सु मोटेगी और योशिमासा हयाशी दोनों पिछले साल की नेतृत्व की दौड़ में शामिल थे। अनुभवी राजनेता मोटेगी एलडीपी के नीति प्रमुख भी रह चुके हैं। अन्य संभावित

दावेदारों में पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची और कृषि मंत्री शिंजीरो कोइजुमी भी शामिल हैं। जुलाई में हुए चुनाव में एलडीपी को मिली हार 2024 के प्रतिनिधि सभा चुनाव में भी इसी तरह के नतीजों के बाद आई है, जिससे सत्तारूढ़ गुट संसद के दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है। 1955 में एलडीपी की स्थापना के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि पार्टी के प्रेसिडेंशियल चुनाव की वकालत करने वाले सांसद सोमवार को एलडीपी मुख्यालय जाएंगे और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियम कहते हैं कि अगर पार्टी के अधिकांश सांसद और पार्टी के प्रीफेक्चुरल चैप्टर जल्द चुनाव के पक्ष में हैं तो पार्टी को चुनाव कराना होगा। इशिबा के इस्तीफे के बाद पार्टी को उनके उत्तराधिकारी नामित करने के लिए चुनाव कराना होगा।

एक्स पर नैरेटिव लोग तय करते हैं, मस्क ने पीटर नवारो को दिया जवाब

एजेंसी

नई दिल्ली । टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नैरेटिव लोग तय करते हैं। मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बीच यह बयानबाजियां भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर विवाद के बीच हुआ।

नवारो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, भारत केवल लाभ के लिए रूसी तेल खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने तेल की कोई खरीद नहीं की। भारत सरकार की स्पिन मशीन तेज गति से चल रही है। यूक्रेनियों को मारना बंद करो। अमेरिकी नौकरियां छीनना बंद करो। कम्युनिटी नोट्स द्वारा एक्स के फैक्ट चेक ने नवारो के कमेंट को मिसलीडिंग बताते हुए फ्लैग किया और कहा कि भारत की संप्रभु ऊर्जा खरीद अंतरराष्ट्रीय कानून का अनुपालन करती है। नवारो

ने इसके बाद मस्क की क्रैप नोट्स की अनुमति देने के लिए आलोचना की।मस्क ने जवाब दिया, इस मंच पर, लोग ही नैरेटिव तय करते हैं।आप किसी भी तर्क के सभी पक्षों को सुनें। कम्युनिटी नोट्स सभी को सही करता है, कोई अपवाद नहीं। नोट्स डेटा और कोड सार्वजनिक स्रोत हैं। ग्रोक आगे फैक्ट-चेकिंग प्रदान करता है। भारत सरकार ने भी चल रहे विवाद के बीच नवारो के बयानों को खारिज कर दिया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उन्हें गलत और भ्रामक बयान बताया। नवारो ने पहले भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी, तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में रूसी और चीनी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकातों पर सवाल उठाया था और कहा था कि भारत को रूस के साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ रहने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को एक बेहद खास रिश्ता बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। ट्रंप चीन के हाथों भारत को खोने वाली अपनी पिछली टिप्पणी से पीछे हटते हुए दिखे और कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा दोस्त बना रहूंगा। इस टिप्पणी के कुछ घंटों बाद, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं।

इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम 'फेल', हूती विद्रोहियों ने एयरपोर्ट पर की ड्रोन स्ट्राइक

एजेंसी

यरूशलम। इजरायल हवाई अड्डा प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि रामोन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हूती विद्रोहियों ने इजरायल के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था।

इजरायली सेना ने कहा कि एक ड्रोन देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रहा और देश के दक्षिणी एयरपोर्ट पर गिरा। इस घटना से एयरपोर्ट की इमारत की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई। इस हमले के बाद कुछ समय के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन्स को रोक दिया गया। इजरायल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि कम से कम दो लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं।

उन्हें पास के रिसॉर्ट शहर ऐलात के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली सेना ने कहा कि वह यमन से किए गए ड्रोन हमले की जांच कर रही है, जिसके कारण विमानों की रवानगी और लैंडिंग लगभग दो घंटे तक रोक दी गई। इस हमले के बाद एक बार फिर इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि, इजरायली सेना ने दावा किया कि ड्रोन का पता वायु सेना प्रणालियों ने लगाया था। लेकिन, उस ड्रोन के खतरे को सही से नहीं आंका गया, जिस कारण जवाबी कार्रवाई करने वाले सिस्टम ने खुद को एक्टिवेट नहीं किया। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। एक बयान में हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार इजरायल को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। उनका दावा है कि इजरायल के गाजा पर हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसके जवाब में इजरायल भी लगातार मिसाइल और अन्य हवाई हमले कर रहा है। इजरायल का कहना है कि उसकी तरफ किए गए हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आठ माह में आतंकवादियों ने 605 हमले किए, 138 नागरिक मारे गए और 352 घायल

एजेंसी

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इस साल आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है। साल के पहले आठ महीनों में 605 हमले हुए। इनमें 138 नागरिक मारे गए और 352 घायल हुए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय पुलिस कार्यालय (सीपीओ) के आंकड़ों में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान आतंकवाद से संबंधित मामलों में 351 संदिग्ध आतंकवादियों के नाम दर्ज किए गए। सुरक्षा अभियानों में 32 आतंकवादी मारे गए

और पांच अन्य गिरफ्तार किए गए। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि प्रांत के पुलिस बल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन हमलों में 79 जवान मारे गए और 130 घायल हुए। अकेले अगस्त में ही पूरे प्रांत में 129 आतंकवादी घटनाएं हुईं। इन हमलों में 17 नागरिकों की जान गई और 51 घायल हुए। इसी महीने, 186 संदिग्धों की पहचान की गई, जबकि मुठभेड़ों में आठ आतंकवादी मारे गए। जिलेवार विवरण से पता चलता है कि अगस्त में बन्नू में सबसे अधिक 42 हमले हुए।

अमेरिका लगा सकता है रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध, ट्रंप ने दिए संकेत

एजेंसी

न्यूयॉर्क । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के अड़ियल रवैये के चलते यह कदम उठाने की बात कही है। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि ये नए प्रतिबंध क्या होंगे। वाशिंगटन में एक पत्रकार के सवाल पर कि क्या वह प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू करने के लिए तैयार हैं, इस पर ट्रंप ने संक्षेप में जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। हालांकि, उनके इस छोटे से जवाब से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह किस तरह के नए प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं या किन देशों को इसका निशाना बनाया जाएगा। अगस्त के मध्य में जब एक पत्रकार ने उनसे चीन को लेकर सवाल किया (जिसे रूसी तेल खरीदने पर अब तक दंडात्मक टैरिफ

(शुल्क) से छूट मिली हुई है) तो ट्रंप ने जवाब दिया था, मुझे दो या तीन हफ्तों में इस पर कुछ सोचना पड़ सकता है या कुछ करना पड़ सकता है दूसरी ओर, उन्होंने तेल प्रतिबंधों के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया था और उस पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया था।ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी शांति कूटनीति के तहत तीन सप्ताह पहले एक शिखर सम्मेलन किया था। हालांकि, उन्होंने इस मुलाकात से बड़ी उम्मीदें जताई थीं, लेकिन पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है और रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए हैं।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हासेट ने कहा कि रूसी हमलों में वृद्धि के बाद मुझे यकीन है कि आज और कल प्रतिबंधों के स्तर और समय के बारे में बहुत चर्चा होगी। सीबीएस न्यूज के एक इंटरव्यू में नई प्रतिबंधों के समय के बारे में पूछे जाने पर हासेट ने कहा, ÷यह अंततः राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। लेकिन हां, यह बहुत निराशाजनक स्थिति है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूसी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध बढ़ाने का एक संभावित तरीका सुझाया, जिसमें यूरोपीय संघ (ईयू) को अमेरिका के साथ मिलकर माध्यमिक प्रतिबंध लगाने के लिए शामिल करना जुड़ा है, ताकि मास्को पर बातचीत के लिए दबाव बनाया जा सके।

अमेरिका की इमिग्रेशन रेड से दक्षिण कोरिया में हड़कंप, निवेशकों की चिंता बढ़ी

एजेंसी

सियोल/वॉशिंगटन। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में दो दक्षिण कोरियाई कंपनियों द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट पर हुई इमिग्रेशन रेड ने सियोल में राजनीतिक और निवेश हलचल पैदा कर दी है। यह छापा ऐसे समय पर पड़ा है जब राष्ट्रपति ली जे म्युंग हाल ही में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और दोनों देशों के बीच बड़े निवेश समझौते का ऐलान किया गया था।अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिकी एजेंसियों ने प्लांट के निर्माण स्थल से करीब 300 दक्षिण कोरियाई नागरिकों को हिरासत में लिया। इनमें से ज्यादातर हुंडई मोटर और एलजी एनर्जी सॉल्यूशन की संयुक्त परियोजना में काम कर रहे थे। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कर्मचारी किस वीजा श्रेणी के तहत अमेरिका आए थे और क्या उन्हें वहां कार्य करने की वैध अनुमति थी।दक्षिण कोरियाई सरकार ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की रिहाई के लिए कूटनीतिक स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है और जैसे ही प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होंगी, उन्हें स्वदेश लाने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजी जाएगी। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सियोल और वॉशिंगटन ने हालिया शिखर बैठक में रणनीतिक गठबंधन और व्यापारिक

साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश की थी। इस समझौते के तहत अमेरिका में विस्तार कर रही कोरियाई कंपनियों के लिए 350 अरब डॉलर का फंड बनाया गया है, जिसमें से 150 अरब डॉलर शिपबिल्डिंग सेक्टर के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों ने भी अमेरिका में 150 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष निवेश का वादा किया है।

फ्रांसीसी संसद में प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

एजेंसी

पेरिस। फ्रांस में राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आज फ्रांसीसी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने जा रहा है। विपक्षी दलों द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव यदि पास हो जाता है, तो यह सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा और प्रधानमंत्री

को अपने पद से हटना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव के चलते राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। यदि सरकार गिरती है, तो उन्हें तुरंत एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा और एक स्थिर सरकार बनाने की कोशिश करनी होगी, जो कि मौजूदा राजनीतिक ध्रुवीकरण के माहौल में आसान नहीं होगा इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों के पास कुछ विकल्प हैं। वह अपनी ही पार्टी या गठबंधन के किसी नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यदि कोई भी विकल्प सफल नहीं होता है, तो अंतिम उपाय के रूप में वह संसद को भंग कर सकते हैं और नए सिरे से चुनाव की घोषणा कर सकते हैं।

यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले से अमेरिका में हलचल, ट्रंप ले सकते हैं बड़ा फैसला

एजेंसी

कीव (यूक्रेन)/ वाशिंगटन (अमेरिका)। रूस के यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले से वाशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप से व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों ने सवाल किया-अब मॉस्को के प्रति क्या इरादा है? ट्रंप ने कहा कि वह बड़ा फैसला लेंगे। यूक्रेन के अखबार कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, हम अब इस प्रतिस्पर्धा में हैं कि यूक्रेनी सेना कितने समय तक टिक सकती है, बनाम रूसी अर्थव्यवस्था कितने समय तक टिक सकती है? बेसेंट ने कहा कि यही नहीं, अब अमेरिका रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी करने को तैयार है।

जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग प्रमुख से बातचीत की

उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ आगे आकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर और प्रतिबंध और अतिरिक्त टैरिफ लगाएं तो रूसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी और मजबूर होकर राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा। बेसेंट ने कहा कि हमले के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन से चर्चा की है। उन्होंने कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। हम रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपने यूरोपीय सहयोगियों को भी साथ लाने की ज़रूरत है।

अमेरिकी दूतावास ने हमले की निंदा की

इस हमले पर कीव स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर हमले में एक मां और एक शिशु की बेवजह हत्या और अभूतपूर्व पैमाने पर विनाश की निंदा की है। यूक्रेन के लिए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग ने भी सोशल मीडिया पर लिखाऱ किसी भी युद्ध में खतरा तनाव का बढ़ना होता है। ऐसा लगता है कि रूस युद्ध को और बढ़ा रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला कीव स्थित कैबिनेट के कार्यालय पर हुआ है। केलॉग ने इसके लिए रूस को चेताया भी है।

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट बोले- कार्रवाई का वक्त आ गया

इस हमले पर कैपिटल हिल में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। रिपब्लिकन सीनेटर थॉम टिलिस (आर-एनसी) ने सोशल मीडिया पर लिखाऱ राष्ट्रपति ट्रंप तीन हफ्ते पहले पुतिन से मिले थे। तब से, पुतिन अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपने साथी सत्तावादियों से मिले हैं। फिर वह अपने अवैध आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले को मंजूरी देने के लिए मॉस्को लौट आए। अब इस झूठे और हत्यारे को रोकने का समय आ गया है। सीनेटर जॉन कॉर्निन (रिपब्लिकन-टेक्सास) ने भी इसी भावना को दोहराया। विदेश नीति पर अग्रणी डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन (डेमोक्रेट-न्यू हैम्पशायर) ने रूस तुरंत प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहाऱ पुतिन ने निर्दोष यूक्रेनियों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। जब तक ट्रंप कार्रवाई नहीं करते, ये हमले जारी रहेंगे। अब और समय सीमा नहीं बढ़नी चाहिए। रिपब्लिकन कांग्रेसी ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक (रिपब्लिकन-पेंसिल्वेनिया) ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य बताया। उन्होंने कहा, यह सैन्य रणनीति नहीं है। यह आतंक है। जानबूझकर और सोची-समझी रणनीति। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने रूस के देश पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद कैबिनेट भवन के अंदर हुई तबाही दिखाई। इस हवाई हमले में कीव के मध्य भाग में चार लोग मारे गए हैं।

देश का दर्पण न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, address- 14 no V ki sikar Road